● वर्ष-5

● अंक-286

रायपुर, शुक्रवार
17 जुलाई 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

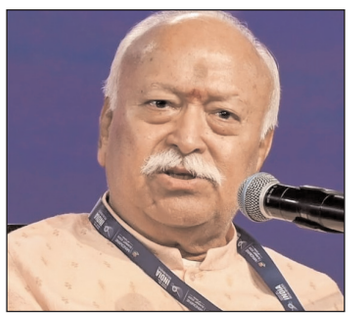


पेज-8>> रिमझिम बारिश के बीच...

आधी आबादी से भागवत पहली बार करेंगे मातृत्व पर बात

उत्तर भारत की 280 महिला प्रतिनिधि लेंगी हिस्सा विश्व मांगल्य सभा का 24 जुलाई को कार्यक्रम

नई दिल्ली। मानसून सत्र में आधी आबादी के सशक्तीकरण के लिए महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक लाए जाने की चर्चा के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। 24 जुलाई को विश्व मांगल्य सभा की ओर से मातृत्व विषय पर आयोजित सम्मेलन में भागवत महिला शक्ति से जुड़े मातृत्व और पारिवारिक मूल्यों पर व्याख्यान देंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के सौ साल में यह पहला अवसर होगा जिसमें कोई संघ प्रमुख आधी आबादी से सीधा संवाद करेगा।



डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उत्तर भारत के विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों से करीब 280 प्रतिनिधि महिलाएं भाग लेंगी। इनमें जम्मू-कश्मीर, लेह लद्दाख, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से जुड़े अवध, मालवा, महाकौशल, गुजरात, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा की महिलाएं शामिल होंगी। यह कार्यक्रम संघ के शताब्दी वर्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की शृंखला का हिस्सा है।

इससे जुड़ा भागवत का दूसरा व्याख्यान 25 व 26 जुलाई को हैदराबाद में होगा। इसमें महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों की प्रतिभागी हिस्सा लेंगी। विश्व मांगल्य सभा की राष्ट्रीय संगठन मंत्री वृषाली जोशी के मुताबिक कार्यक्रम में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में राजनीति, अर्थव्यवस्था, मनोरंजन, खेल और समाज से जुड़ी प्रमुख महिला नेतृत्व शामिल होंगी।

संयोग...यह दिलचस्प संयोग है कि जब संघ प्रमुख पहली बार आधी आबादी के साथ सीधा संवाद कर रहे होंगे, तब मोदी सरकार मानसून सत्र में महिला आरक्षण के लिए राजनीतिक जंग लड़ रही होगी। गौरतलब है कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी मानसून सत्र में विधेयक को अमली जामा पहनाने की रणनीति बनाने केलिए 21 जुलाई को राजग की बैठक बुलाई गई है। आमतौर पर सत्र के दौरान राजग की बैठकों से दूरी बनाने वाले पीएम मोदी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे।

विश्व मांगल्य सभा के 16 वर्ष पूरे

नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, विश्व मंगल्या सभा की राष्ट्रीय संगठनात्मक सचिव डॉ. वृषाली जोशी ने पिछले 16 वर्षों में संगठन की यात्रा का संक्षिप्त विवरण दिया।

विश्व मंगल्या सभा की स्थापना 19 जनवरी, 2010 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुई थी और यह सांस्कृतिक और बौद्धिक पहलों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।संगठन का मार्गदर्शक आदर्श वाक्य, ना मतु पर दैवतम् (मां से बड़ा कोई देवता नहीं है), परिवार और राष्ट्र निर्माण में माताओं की केंद्रीय भूमिका को पहचानने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डॉ. जोशी ने बताया कि यह संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और महिलाओं में सकारात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने पर ध्यान केंद्रित करता है। आज, इसकी भारत के 33 क्षेत्रों में संगठनात्मक उपस्थिति है, जिसे लगभग 3,500 पदाधिकारियों और लगभग 6 लाख महिला सदस्यों का समर्थन प्राप्त है।

विधानसभा से पारित हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज %छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026% पारित किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां जोखिम आधारित एवं विश्वास आधारित बिजनेस परमिशन सिस्टम लागू होगा।

इस अधिनियम का उद्देश्य उद्योगों और कारोबार की स्थापना तथा संचालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। यह अनावश्यक अनुपालनों को कम करेगा और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पारदर्शी वातावरण बनाएगा। अधिनियम के तहत उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार और गतिविधियों के जोखिम के आधार पर होगा। कम जोखिम वाले छोटे कारोबारों को सरल और त्वरित मंजूरी मिलेगी। अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए तकनीकी परीक्षण और समयबद्ध

छोटे कारोबारों को मिलेगी आसान मंजूरी



स्वीकृति की व्यवस्था जारी रहेगी। इससे छोटे कारोबारियों को जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। कम जोखिम वाले उद्यमों में बार-बार विभागीय निरीक्षणों के स्थान पर सेल्फ सर्टिफिकेशन या अधिकृत पेशेवरों द्वारा प्रमाणन होगा। इससे अनुमतियों की प्रक्रिया तेज, सरल और अधिक जवाबदेह बनेगी।

प्रक्रियाओं का सरलीकरण

अधिनियम हर वर्ष लाइसेंस या अनुमति के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त करता है। अब जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली लागू होगी। इससे उद्यमियों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलेगी। वे अपने कारोबार के विस्तार पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। एमएसएमई इकाइयों के लिए जल प्रदाय अनुमति स्व-घोषणा पर मिलेगी।

निगरानी और लाभ

सोसायटी या फर्म का पंजीयन समयबद्ध प्रक्रिया से होगा। भवन अनुज्ञा सेल्फ सर्टिफिकेशन या विशेषज्ञ प्रमाण-पत्र के आधार पर मिलेगी। निर्धारित समय-सीमा में निर्णय न होने पर अनुमति स्वत: स्वीकृत मानी जाएगी। राज्य के 8 विभागों की 43 सेवाएं इस प्रणाली में शामिल की गई हैं। इस सुधार से 15 लाख से अधिक एमएसएमई को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

प्लास्टिक पर अशासकीय संकल्प सहमति के बाद लिया वापस

रायपुर। प्लास्टिक न केवल प्रदेश के लिए, बल्कि देश-दुनिया के लिए भी एक बड़ी समस्या है. आलम यह है कि न केवल यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि जानवरों के साथ-साथ इंसानों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है. शोध बताते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक हमारे दिमाग तक प्रवेश कर चुका है.प्लास्टिक से होने वाले गंभीर नुकसान को देखते हुए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर विधानसभा में अशासकीय संकल्प लेकर आए थे. विषय पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष इसकी गंभीरता को लेकर एकमत से इसके निपटान के साथ कड़ी कार्रवाई को लेकर समर्थन जताया. पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्लास्टिक पर कड़े प्रतिबंध लगाने अशासकीय संकल्प लाया गया. उसे मेरे वक्तव्य और आग्रह के बाद अजय चंद्राकर ने वापस ले लिया है. यह सच है कि छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक वर्तमान में एक बड़ी समस्या है. और यह पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है. प्लास्टिक कचरे का बेहतर निपटान कैसे हो सकता है. विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कैसे हो सकता है।

महाप्रभु के स्वागत में झूमे देश-विदेश के भक्त

भुवनेश्वर। पूरे देश में आज आस्था और भक्ति का अनुपम नजारा देखने को मिल रहा है, जहाँ विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ हो गया है। ओडिशा के पुरी स्थित श्री मंदिर में आयोजित होने वाली इस पावन यात्रा के दर्शन के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। आज से शुरू हुई यह पावाना यात्रा 27 जुलाई को नीलाद्री बीजे के साथ संपन्न होगी। सुबह से ही भारी बारिश के बावजूद भक्तों का हौसला डगमगाया नहीं है। गीली सड़कों और बौछारों के बीच लाखों हाथ भगवान के विशाल रथों की पवित्र रस्सियों को थामने के लिए कतारों में मुस्तैद दिखे। शंखों की आवाज, घंटों की गूंज और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है।

इस पावन अवसर पर प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने भी महाप्रभु के दर्शन किए। उन्होंने अभिभूत होकर कहा, मैंने पहले भी कई बार इसके लिए गाया है, लेकिन पहली बार साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। यहाँ मैंने जो कुछ भी देखा है, वह जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। मुझे यहाँ का मैनेजमेंट बहुत पसंद आया। आस्था का यह रंग वैश्विक स्तर पर भी दिखा, जहाँ एक विदेशी भक्त ने भावुक होकर कहा, मैं भगवान जगन्नाथ से



प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारी सेवा स्वीकार करें। मैं अपने गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने की क्षमता दें; हम बस उनके दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं।

पुरी मंदिर के सिंहद्वार पर महाप्रभु जगन्नाथ के नंदीघोष, भाई बलभद्र के तालध्वज और बहन सुभद्रा के दर्पदलन रथ को पूरी भव्यता के साथ खड़ा किया गया है। रथयात्रा से पहले वैदिक मंत्रोच्चार और हवन-यज्ञ के बीच तीनों रथों की विधिवत प्रतिष्ठा संपन्न की गई। इस दौरान सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए नंदीघोष पर श्रीहनुमान, तालध्वज पर श्रीनृसिंह और देवदलन रथ पर मां भुवनेश्वरी की स्थापना की गई। रथ यात्रा के दौरान ओडिशी नृत्यांगनाओं का मनमोहक नृत्य एक प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा के रूप में जीवंत हो उठा, जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और ओडिशा की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। धार्मिक अनुष्ठान के बाद तीनों विग्रह अलग-अलग रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए हर कोई इसके लिए बेताब नजर आ रहा है।

यात्रा से ठीक पहले केंद्रीय मंत्रियों और स्थानीय मंत्रियों ने पुरी के गोवर्धन पीठ का दौरा कर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ओडिशा के साथ-साथ गुजरात के अहमदाबाद में भी जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है, जहाँ मुख्यमंत्री ने सोने की झाड़ू से रथ का मार्ग साफ कर विशेष पूजा-अर्चना की।

प्रमुख समाचार

पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी रथ यात्रा की शुभकामनाएं

नईदिल्ली। ओडिशा के पुरी में आज से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश और दुनिया भर के श्रद्धालुओं को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर



सभी को बधाई। यह भारत की सदाबहार आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की शानदार अभिव्यक्ति है। रथ यात्रा से जुड़ी परंपराओं ने भारत और दुनिया भर में कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ये विनम्रता, सामूहिक भागीदारी और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक हैं। पीएम मोदी ने सभी की भलाई और खुशहाली के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने कहा, महाप्रभु जगन्नाथ सभी को अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि का आशीर्वाद दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ अवसर पर भारत और दुनिया भर के भक्तों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह भावपूर्ण अवसर भक्त और ईश्वर के मिलन का प्रतीक है और सचमुच अनोखा है।

भाजपा ने उत्तराखंड को पेपर लीक का एपिसेंटर बनाया

नईदिल्ली। शुक्रवार को देहरादून में छात्रों के साथ बातचीत से पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उत्तराखंड पेपर लीक का केंद्र बन गया है और उन्होंने युवाओं के भविष्य को नीलाम न होने देने का संकल्प लिया। गांधी ने कहा कि वह 17 जुलाई को देहरादून का



दौरा कर रहे हैं क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का केंद्र बना दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि UKSSSC (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) की परीक्षाओं को लेकर यहां एक सिस्टम बन गया है, जिसमें पटवारी या लेखपाल जैसे पद मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि अपराधियों द्वारा तय की गई कीमतों पर हासिल किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नकल-रोधी कानून तो बनाया, लेकिन पेपर लीक होने का सिलसिला जारी रहा। गांधी ने कहा कि कानून सिर्फ़ कागज़ों तक ही सीमित रहा, जबकि परीक्षा के पेपर बाज़ार में बिकते रहे। ज़रा सोचिए- एक छात्र सालों तक तैयारी करता है। वह फ़ॉर्म भरता है, फ़ीस देता है और दूर स्थित परीक्षा केंद्र तक जाता है।

राजनाथ सिंह आज एनडीए मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे

नईदिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के मंत्रियों के साथ संसदीय रणनीति पर एक हाई-लेवल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए सरकार के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा।



मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सरकार अपने विधायी एजेंडे की रूपरेखा बताएगी और विपक्षी दलों से उन मुद्दों का विवरण देने की उम्मीद है जिन्हें वे सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। बैठक के सुबह 11 बजे शुरू होने की संभावना है। इस सत्र में कई अहम बिलों पर चर्चा होने की उम्मीद है, और कुछ विपक्षी पार्टियों में हालिया मतभेदों के कारण इसके हंगामेदार रहने की संभावना है। विधानसभा चुनावों में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल-पुथल मची है; पार्टी के 20 सांसदों ने नेशनल सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया में विलय कर लिया है। इन सांसदों ने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

परिसीमन विधेयक पर इंडिया गठबंधन एकजुट : संजय राउत

मुंबई। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन विधेयक पेश किए जाने की संभावना को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी करने वाले किसी भी प्रस्ताव



के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ व्यापक चर्चा की ज़रूरत होगी। राउत ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के एकजुट रुख पर ज़ोर देते हुए कहा कि वे सत्ताधारी सरकार के किसी भी एकतरफ़ा कदम का विरोध करेंगे। राउत ने कहा कि संसदीय सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के किसी भी प्रस्ताव पर सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा के बाद ही विचार किया जा सकता है। इंडिया गठबंधन का कोई भी दल-चाहे वह शिवसेना हो, कांग्रेस हो या एनसीपी-अकेले कोई फ़ैसला नहीं लेगा। परिसीमन विधेयक पर कोई भी फ़ैसला गठबंधन के सभी सहयोगी दल मिलकर लेंगे। परिसीमन के मुद्दे के अलावा, राउत ने हाल ही में नेताओं के दल बदलने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की।

आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार को फिलहाल राहत

नईदिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को फिलहाल राहत मिली है। गुरुवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में आरोप तय करने पर फैसला नहीं सुना सकी। अब अदालत 31 जुलाई को इस पर अगला आदेश देगी।



इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। ईडी ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी का आरोप है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तथ्य सामने आए हैं। यह मामला उस समय का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच रेलवे के होटलों के रखरखाव और संचालन का ठेका निजी कंपनी को देने में अनियमितता की गई। जांच एजेंसियों के अनुसार, आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित दो होटलों के विकास, संचालन और रखरखाव का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया था।

समुद्री शक्ति स्वदेशी रक्षा निर्माण और सामरिक आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक

नीरज कुमार दुबे

भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमता को नई ऊंचाई देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरि को पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट सत्रह ए के तहत निर्मित यह छठा और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत सिर्फ एक नया जहाज नहीं, बल्कि समुद्री शक्ति, स्वदेशी रक्षा निर्माण और सामरिक आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक है। महेंद्रगिरि के नौसेना में शामिल होने के साथ ही भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह केवल अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूरस्थ समुद्री क्षेत्रों में भी अपने हितों की प्रभावी सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है।

हम आपको बता दें कि करीब छह हजार छह सौ सत्तर टन वजन और अट्ठाइस नॉट की अधिकतम गति वाला यह बहुउद्देशीय युद्धपोत आधुनिक समुद्री युद्ध की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इसमें रडार पर कम दिखाई देने वाली स्टील्थ क्षमता, अत्याधुनिक स्वचालित प्रणालियां, हमलों को झेलने की बेहतर क्षमता और पचहत्तर प्रतिशत से अधिक स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं। इसे ब्रह्मोस प्रहारक मिसाइल, लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, बहुउद्देशीय रडार, पनडुब्बी रोधी रक्षा प्रणाली, टारपीडो प्रक्षेपक, स्वदेशी रॉकेट प्रक्षेपक तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस किया गया है। यही कारण है कि यह हवा, समुद्र की सतह और समुद्र के भीतर छिपे दुश्मनों पर एक साथ प्रभावी प्रहार करने में सक्षम है।

हम आपको बता दें कि महेंद्रगिरि को ब्लू वाटर युद्धपोत की श्रेणी में रखा गया है। इसका अर्थ है कि यह केवल तटीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में कई सप्ताह तक लगातार अभियान चलाने की क्षमता रखता है। खोज और बचाव अभियान, मानवीय सहायता, आपदा राहत, समुद्री सुरक्षा तथा हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी तैनाती जैसे दायित्व भी यह समान दक्षता से निभा सकता है। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरि पर्वतमाला के नाम पर रखे गए इस युद्धपोत के प्रतीक चिह्न में दर्शाया गया शिकरा पैनी दृष्टि, धैर्य और निर्णायक प्रहार का प्रतीक है, जो इसकी युद्धक भूमिका को भी



प्रतिबिंबित करता है।

देखा जाये तो महेंद्रगिरि का सामरिक महत्व केवल इसकी मारक क्षमता तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर आज विश्व व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सामरिक प्रतिस्पर्धा का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। ऐसे समय में भारत के पास जितने अधिक आधुनिक और दूर तक अभियान चलाने वाले युद्धपोत होंगे, उतनी ही मजबूत उसकी समुद्री प्रतिरोधक क्षमता होगी। यह युद्धपोत समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, शत्रु की गतिविधियों पर निगरानी, पनडुब्बियों की खोज और आवश्यकता पड़ने पर त्वरित जवाबी कार्रवाई में निर्णायक भूमिका निभाएगा। इससे हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के रूप में और मजबूत होगी।

हम आपको यह भी बता दें कि हाल के महीनों में भारतीय नौसेना का विस्तार अभूतपूर्व गति से हुआ है। 21 जून 2026 को एक साथ तीन महत्वपूर्ण पोत नौसेना में शामिल किए गए थे। इनमें आईएनएस दुनागिरि स्टील्थ युद्धपोत, आईएनएस संशोधक गहरे समुद्र का सर्वेक्षण पोत और आईएनएस अग्रय पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल हैं। इसके पहले 31 मार्च 2026 को आईएनएस मालवन को शामिल किया गया, जबकि साल 2025 में बहुउद्देशीय स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल भी नौसेना का हिस्सा बना। अब महेंद्रगिरि के शामिल होने से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, निगरानी शक्ति और समुद्री उपस्थिति पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हो गई है।

यदि दस वर्ष पहले की तुलना करें तो भारतीय नौसेना में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देता है। तब अधिकांश प्रमुख युद्धपोतों और हथियार प्रणालियों के लिए विदेशी निर्भरता अधिक थी, जबकि आज स्वदेशी डिजाइन, निर्माण और अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोत तेजी से बेड़े में शामिल हो रहे हैं। विमानवाहक पोत, आधुनिक विध्वंसक, स्टील्थ युद्धपोत, पनडुब्बी रोधी पोत, सर्वेक्षण पोत, उन्नत प्रहारक मिसाइल और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों ने नौसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। इस तरह अब भारत केवल समुद्री सुरक्षा करने वाला देश नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने वाली महत्वपूर्ण समुद्री ताकत के रूप में उभर चुका है।

साथ ही महेंद्रगिरि का नौसेना में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना अब केवल नारा नहीं, बल्कि समुद्र की लहरों पर दौड़ती वास्तविक शक्ति बन चुकी है। यह युद्धपोत आने वाले वर्षों में भारत की समुद्री सुरक्षा का मजबूत प्रहरी बनने के साथ साथ स्वदेशी रक्षा निर्माण की सफलता का भी सबसे प्रभावशाली उदाहरण साबित होगा।



डौंडी नगर पंचायत के पास कचरे का पहाड़

बालोद। जिले के डौंडी नगर पंचायत की अव्यवस्था के चलते अवारी नाला के पास कचरे का पहाड़ बन गया है। इस डंपिंग यार्ड की बदबू और बारिश में बहकर आ रहे कचरे से ग्रामीणों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है, जबकि नगर पंचायत प्रशासन इसे हटाने में लाचार नजर आ रहा है। मामले की गंभीरता के बावजूद, जिम्मेदार अधिकारी डंपिंग यार्ड की सुरक्षा दीवार तक सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। बारिश के समय यहां का कचरा नलों में होकर ग्रामीणों के लिए समस्या पैदा करता है तो वहीं इससे उठने वाली बदबू से भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान हैं। नगर पंचायत के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी का कहना है कि सीमेंट कंपनी से पिछले वर्ष जून महीने में हमने अनुबंध किया था जिसके तहत सीमेंट कंपनियां कचरो को ले जाने वाली थी लेकिन उनके द्वारा किसी तरह का कोई पहल अब तक नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि हम आसपास अन्य जगह देख रहे हैं लेकिन कचरा डंप के लिए निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। यह कूड़े का पहाड़ इतना बड़ा हो चुका है कि अवारी नाला किनारे इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वहीं कचरा डंप जगह पर दीवार है या नहीं इसकी भी जानकारी सीएमओ को नहीं है, उन्होंने श्मशान की दीवार को डम्पिंग क्षेत्र की दीवार बता दिया, जहां कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि वहां अब तक कोई निर्माण कार्य कचरों के उचित प्रबंधन को लेकर नहीं किया गया है। वहीं पास के पंचायत भी इसके लिए आपत्ति जता रहे हैं। नगर पंचायत डौंडी से लगे ग्राम पंचायत अवारी की सरपंच अमिता मंडावी ने बताया कि कचरे का ढेर गांव की सरहद से लगा हुआ है जिसके कारण काफी समस्या होती है जब नाले में पानी आता है तो कचरा भी बस्तियों और खेतों तक पहुंच जाता है। अधिकारियों का कहना है कि समय-समय पर उस जगह की सफाई कराई जाती है। लेकिन मौके पर कचरे का पहाड़ साफ देखा जा सकता है।

38 सिविल जजों को पदोन्नति, जूनियर से बने सीनियर डिवीजन जज



बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में पदस्थ 38 सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर पदोन्नत किया है। सभी को मार्च और अप्रैल की विभिन्न तिथियों से पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सिविल जज जूनियर अंजली पांडेय, अंकिता अग्रवाल, दिव्या गोयल, ऐश्वर्या दीवान, शैलेश कुमार वशिष्ठ, आफरीन बानो, हर्षि अग्रवाल, मीनू नंद, प्रज्ञा अग्रवाल, स्वर्णा देहरे, काम्या अय्यर, सारिका नंदे, अजय सिंह मीणा, रश्मि मिश्रा, शाश्वत दुबे, कोनिका यादव, आशीष कुमार चांदहे, गुरु प्रसाद देवांगन, कुमुदिनी गर्ग, अंकिता यदु, उन्नति महेश्वर, सिद्धार्थ आनंद सोनी, तनया ब्राह्मी, नीति, मनीष कुमार, साक्षी ध्रुव, पार्थ दुबे, जेनिफर लकड़ा, धारिणी राणा, प्रांजलि नेताम, राजेश खलको, अजय लकड़ा, ध्रुवराज ग्वाल, शिवेंद्र कुमार टेकाम, श्वेता ठाकुर, पुनीत तिग्गा, डिंपल और प्रवीण कुजूर को सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर पदोन्नत किया गया है।

राम मंदिर चंदा-चढ़ावा विवादः छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने उठाए बड़े सवाल

मोदी-शाह से जवाब और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग



दंतेवाड़ा/बालोद/महासमुंद। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी और ऋस्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी जिलों में कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाया कि भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के संगठनों ने वर्षों तक भगवान राम के नाम पर आंदोलन चलाया और जनता से चंदा लिया। अब उसी चंदे और चढ़ावे की चोरी हो रही है।

दंतेवाड़ा में नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि भगवान श्रीराम करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और नैतिक चेतना के प्रतीक हैं, इसलिए उनके नाम पर जुटाए गए धन के उपयोग में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। चंदन कश्यप ने कहा कि देशभर के गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं और श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई, गहने और बचत राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धापूर्वक दान में दिए थे। उन्होंने कहा कि करोड़ों रामभक्त यह जानना चाहते हैं कि भगवान राम के नाम पर जुटाया गया चंदा और चढ़ावा आखिर किसके संरक्षण में कथित रूप से गड़बड़ी का शिकार हुआ। बालोद में महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर ने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर राम मंदिर के नाम पर पहले से एकत्र किए गए चंदे का हिसाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के संगठनों ने लगभग तीन दशकों तक भगवान राम के नाम पर राजनीति की, देश के गरीब व मध्यम वर्ग से राम के नाम पर चंदा एकत्र किया और इसी आंदोलन के आधार पर सत्ता प्राप्त की। आज वही करोड़ों रामभक्त यह पूछने को मजबूर हैं कि भगवान राम के नाम पर जुटाया गया चंदा और चढ़ावा आखिर किसके संरक्षण में लूटा गया?

पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर ने कहा कि इन घोटालों को आरएसएस भाजपा का संरक्षण रहा है। भाजपा ने देवद्रव्य चोरी करने के महापाप का संरक्षण किया है। राम मंदिर न्यास ट्रस्ट का गठन गृहमंत्री अमित शाह ने किया था इसलिए वहां पर घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी मोदी और शाह की बनती है।

महासमुंद जिले में कांग्रेस कमेटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई दान में दी थी। अब चढ़ावे में कथित चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों के सामने आने से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रेसवार्ता में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी ने दावा किया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों और ट्रस्टियों के इस्तीफे, मीडिया रिपोर्टों में सामने आए वित्तीय आरोप और ऑडिट से जुड़े मुद्दे मामले को और गंभीर बनाते हैं। अगर सब कुछ पारदर्शी है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने से परहेज क्यों किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए। पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ स्ह्रङ्क दर्ज कर कार्रवाई की जाए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए। राम मंदिर के लिए प्राप्त चंदे, चढ़ावे और खर्च का स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

बलरामपुर में 2 प्रयोगशाला सहायक निलंबित

दोनों शिक्षकों पर अनुशासनहीनता का आरोप



बलरामपुर। शिक्षकों के ऊपर बच्चों को पढ़ाने की न सिर्फ जिम्मेदारी होती है, बल्कि बच्चों को अच्छे आचरण सिखाने का भी जिम्मा होता है। लेकिन जब शिक्षक ही अच्छे आचरण छोड़ स्कूल परिसर में विवाद और झगड़ा करने लगें तो बच्चों पर इसका बुरा असर होता है। बीते दिनों वाड्रफनगर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर में ऐसा ही एक विवाद सामने आया। यहां प्रभारी प्राचार्य और एक व्याख्याता के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो प्रयोगशाला सहायकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर के द्वारा पेश किए गए जांच प्रतिवेदन के मुताबिक, विषय कालखंड की समय-सारणी को लेकर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य अनन्त कुमार यादव और व्याख्याता इजहारूल हक अंसारी के साथ अयोध्या प्रसाद यादव एवं विजय कुमार यादव, प्रयोगशाला सहायक के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। इसकी पुष्टि जांच में हुई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार इस घटना से विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। साथ ही स्कूल में चल रही पढ़ाई-लिखाई का काम भी बाधित हुआ। इसके साथ ही बच्चों के बीच ये संदेश गया कि शिक्षकों के बीच ही अनुशासन की कमी है। इस संबंध में बलरामपुर जिला शिक्षा अधिकारी एमआर यादव ने कहा, %%शिक्षा विभाग के द्वारा प्रारंभिक जांच में पाया गया कि उक्त कृत्य शासकीय सेवक के लिए अपेक्षित अनुशासन, मर्यादा और सेवा आचरण के प्रतिकूल है। प्रथम दृष्टया यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन पाए जाने पर दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-14 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाई की गई। नियम-9(1)(क) के तहत जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अयोध्या प्रसाद यादव एवं विजय कुमार यादव, दोनों प्रयोगशाला सहायकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

5 करोड़ की सौर सिंचाई योजना बनी शो-पीस



दंतेवाड़ा। जिले में सिंचाई को लेकर किसान परेशान हैं। सालभर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से बालुद में करीब 5 करोड़ की लागत से सौर सिंचाई योजना लाई तो गई लेकिन 2 वर्षों से किसानों को ही इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना के तहत 65 किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वर्तमान में परियोजना बंद पड़ी है और किसान फिर से इसे शुरू कराने की मांग कर रहे हैं।

यह योजना जिला प्रशासन द्वारा क्रीड़ा विभाग, जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के संयुक्त समन्वय से शुरू की गई थी।

इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के माध्यम से शंखिनी नदी से पानी उठाकर पाइपलाइन के जरिए किसानों के खेतों तक पहुंचाना था, ताकि किसान वर्ष में एक के बजाय तीन फसलें ले सकें और सब्जी उत्पादन कर अपनी आय बढ़ा सकें। योजना शुरू करने से पहले प्रशासनिक टीम ने सर्वे कर ग्राम पंचायत बालुद का चयन किया।

इसके बाद सोलर प्लांट, पंप, पाइपलाइन और अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण पूरा किया गया। किसानों को उम्मीद थी कि अब उन्हें स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी और खेती की तस्वीर बदलेगी। हालांकि, वर्तमान में योजना बंद होने से किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन खेतों तक बिछा दी गई है, लेकिन लंबे समय से उसमें पानी नहीं आया।

किसानों के अनुसार योजना के प्रचार-प्रसार के दौरान उन्हें सालभर सिंचाई सुविधा का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब वे फिर से केवल बारिश आधारित खेती पर निर्भर हैं। समस्या को लेकर कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और अधिकारियों से चर्चा भी की गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया।

स्कूल में छात्र ने अपने सहपाठियों को काटा, पहुंची स्वास्थ्य विभाग



धमतरी। जिले के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सिलौटी में आज उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक स्कूली छात्र ने अचानक अपना व्यवहार बदलते हुए सहपाठियों को काटना शुरू कर दिया। इस घटना में एक दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए, जिन्हें एहतियात के तौर पर रेबीज रोधी टीका लगाया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, संबंधित छात्र को करीब तीन वर्ष पहले एक रेबीज संक्रमित कुत्ते ने काट लिया था। उस समय उसे चिकित्सकीय सलाह के अनुसार रेबीज के सभी आवश्यक टीके लगाए गए थे। हालांकि, स्कूल में अचानक उसके स्वभाव में बदलाव देखने को मिला और उसने आसपास मौजूद सहपाठियों को काटना शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया। घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया और सभी प्रभावित छात्रों को रेबीज संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं, काटने वाले छात्र को बेहतर चिकित्सकीय परीक्षण और उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले का जायजा लेते हुए आवश्यक चिकित्सकीय एवं एहतियाती कार्रवाई शुरू कर दी। उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह पुष्टि नहीं हुई है कि छात्र की वर्तमान स्थिति का संबंध तीन वर्ष पहले हुई रेबीज की घटना से है। इस संबंध में चिकित्सकीय जांच और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नवपदस्थ एसपी राय गौरव ने ग्रहण किया पदभार

बलौदाबाजार-भाटापारा। भारतीय पुलिस सेवा (भापुसे) 2019 बैच के वरिष्ठ अधिकारी राय गौरव रामप्रवेश ने आज जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के नए पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पूर्व राय गौरव रामप्रवेश जिला दंतेवाड़ा में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। पुलिस कार्यालय बलौदाबाजार पहुंचने पर निवर्तमान पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने विधिवत रूप से नए एसपी को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का चार्ज सौंपा। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया। इस दौरान अभिषेक सिंह (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार), हेमसागर सिदार (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भाटापारा), तारेश साहू (अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भाटापारा), कौशल किशोर वासनिक (उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी, कैंप कसडोल), संजय साहू (उप पुलिस अधीक्षक यातायात)उपस्थित थे।

सेलेक्टेड स्वाइल की जगह तालाब की कीचड़युक्त मिट्टी से कर दिया अर्थ वर्क

गरियाबंद। तालाब सौंदर्यीकरण के लिए राजिम पालिका ने मेला स्थल को जोड़ने वाली पक्की सड़क की गुणवत्ता से समझौता कर लिया। 24 करोड़ के पक्की सड़क के सेलेक्टेड स्वाइल के नाम पर तालाब की मिट्टी डाल दिया गया। धर्म नगरी राजिम में पालिका और पीडब्ल्यूडी का समन्वय चर्चा का विषय बन गया है। नगर के शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण में सहयोग के बदले पालिका ने सड़क ठेकदार को तालाब की मिट्टी दे दिया। हैरानी की बात है कि तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ तो वही सड़क निर्माण के लिए 24 करोड़ की मंजूरी हुई है। दोनों विभाग में कार्यों के लिए अलग-अलग मापदंड तय हैं। बावजूद इसे दो विभागों के निर्माण कार्य में अनोखा समन्वय की मिशाल बनाने की कोशिश की गई। इस अनूठे समन्वय से नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई गई और निर्माण कार्य की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होगा उसे भी समझिए। नियम के मुताबिक, पालिका की मिट्टी का उपयोग दूसरा विभाग नहीं कर सकता पर इस पालिका के अपने ही दलील है।

जीपीएम जिले में एक कमरा और कई क्लास, ये है शिक्षा का हाल

जीपीएम। छिंदपानी में जर्जर होने के कारण माध्यमिक शाला स्कूल भवन को तीन साल पहले डिस्मेंटल कर दिया गया था, लेकिन अब तक नए भवन का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। इसका खामियाजा यहां पढ़ने वाले विशेष संरक्षित बैगा जनजाति के छात्र-छात्राओं को उठाना पड़ रहा है। वर्तमान में माध्यमिक शाला के 20 और प्राथमिक शाला के 16 यानी कुल 36 छात्र-छात्राएं प्राथमिक शाला के एक ही भवन में एक साथ बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कम जगह होने के कारण, सभी कक्षाएं एक साथ लगाई जाती है। जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। स्कूल परिसर में मौजूद एक अतिरिक्त कमरा भी जर्जर हो चुका है। इस कमरे के अंदर टूटा-फूटा सामान और कबाड़ रखा गया है, जबकि उसके बाहरी गलियारे में अस्थायी रसोई बनाकर मध्यान्ह भोजन तैयार किया जा रहा है। इससे बच्चों की सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। भवन निर्माण की मांग और विद्यालय की समस्याओं से संबंधित जानकारी कई बार उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है।

महासमुंद में 50 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

महासमुंद। जिले की बसना थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ बिलासपुर निवासी एक अंतरजिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से गांजा, महिंद्रा बोलेरो और मोबाइल सहित 28 लाख 500 रुपये की संपत्ति जब्त की है। जानकारी के अनुसार, 15 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर पलसापाली बैरियर (पदमपुर रोड) पर नाकाबंदी कर गाड़ियों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान ओडिशा के पदमपुर की ओर से आ रही सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो को रोककर तलाशी ली गई। गाड़ी की पीछे की सीट में छिपाकर रखी गई दो बोरियों से 50 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गांजा ओडिशा से लाकर शिवरीनारायण के पास नायक भैया को सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बसना थाना में अपराध क्रमांक 385/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(C) के अंतर्गत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

कोरबा नपानि के 16 महीनों का महापौर ने पेश किया रिपोर्ट

कोरबा। शहर के पंचवटी में महापौर संजू देवी राजपूत ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी, सीएम विष्णुदेव साय सहित स्थानी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के नेतृत्व में नगर पालिक निगम कोरबा में चहुंमुखी विकास कार्य हो रहे हैं। शहर सरकार के 16 माह के सफल कार्यकाल के दौरान शहर की मूलभूत सुविधाओं सड़क, नाली, पानी और बिजली के क्षेत्रों में व्यापक प्रगति हुई है। मेयर ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी 67 वार्डों मे विभिन्न सुविधाओं के विकास पर लगातार काम किया गया। इस दौरान 537 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए गए। 434 नए विकास कार्यों को स्वीकृति मिली, जिनमें 76 पूरे हो चुके हैं, 149 निर्माणाधीन हैं और 209 कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे महापौर ने कहा कि कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना रही। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत किया गया, बड़े होटल और शादीघरों के कचरा प्रबंधन के लिए सख्ती बरती गई।

आसमान की ओर टकटकी, बारिश की बेरुखी से एमसीबी का अन्नदाता बेहाल

10-15 दिनों से बारिश नहीं होने से धान की फसल सूखने से किसान परेशान हैं.



एमसीबी। खरीफ सीजन के बीच मानसून की सुस्त चाल अब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के किसानों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गई है। ग्रामीण अंचलों में अधिकांश किसान वर्षा आधारित खेती पर निर्भर हैं। शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने बहेड़ा और जवाई धान की बोवाई कर दी थी, लेकिन लगातार बारिश नहीं होने से फसलें मुरझाने लगी हैं। जिन किसानों ने अभी तक बोवाई नहीं की है, वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं।

लगभग 10 दिनों से बारिश नहीं हुई है। जिन खेतों में धान की रोपाई की गई थी, वहां पौधे सूखने लगे हैं। हल-बैल और ट्रैक्टर से खेती का काम बंद पड़ा है। खेतों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। क्षेत्र में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होने से पूरी खेती बारिश पर निर्भर है। यदि जल्द पानी नहीं गिरा तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा-सोनसाय, किसान

यदि बारिश होती तो मजदूरी मिलती और परिवार का पालन-पोषण आसान होता, लेकिन खेती का काम रुकने से आजीविका प्रभावित हो रही है-संगीता, खेतिहर मजदूरगांव के लोग अच्छी बारिश की कामना को लेकर पिछले दो महीने से देवगुड़ी और भगवान शंकर के मंदिर की साफ-सफाई, लिपाई-पुताई और पूजा-अर्चना कर रहे हैं।

गांव के सरपंच ने बताया कि 10 से 15 दिनों से बारिश नहीं हुई है। किसानों द्वारा बोए गए बहेड़ा और जवाई धान अंकुरित होने के बाद भी पर्याप्त नमी नहीं मिलने से सूखने लगे हैं।प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी इंद्रपाल वास्कले ने बताया कि बारिश की कमी से धान की रोपाई प्रभावित हुई है। जिन किसानों के पास निजी सिंचाई व्यवस्था है, वे किसी तरह नर्सरी तैयार कर रोपाई कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर खेती अच्छी बारिश के बिना संभव नहीं है।

यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ सीजन की बुवाई प्रभावित होगी, जिससे धान उत्पादन में कमी आने की आशंका है। किसानों का कहना है कि इसका असर केवल उनकी आय पर ही नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थतंत्र और खेतिहर मजदूरों की रोजी रोटी पर भी पड़ेगा। फिलहाल एमसीबी का अन्नदाता आसमान की ओर टकटकी लगाए झमाझम बारिश का इंतजार कर रहा है।

गेज नदी में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 वाहन जब्त



कोरिया। सोनहत थाना क्षेत्र के नौगई गांव में रेत सप्लाई को लेकर हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में जिला खनिज विभाग ने चिरमी स्थित गेज नदी घाट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत परिवहन में संलिप्त पाए गए पांच गाड़ियों को जब्त किया है। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रेत कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

जिला खनिज विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि चिरमी क्षेत्र के गेज नदी घाट से बिना अनुमति बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला खनिज अधिकारी इंद्र लाल राजवाड़े के नेतृत्व में विभागीय टीम ने घाट पर अचानक दबिश दी। जांच के दौरान नदी तट पर दो ट्रैक्टर और तीन टिपर संदिग्ध परिस्थितियों में खड़े मिले। टीम ने दस्तावेजों की जांच की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभी पांच वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया। इसके बाद वाहनों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई। खनिज विभाग का कहना है कि जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौगई तिहरे हत्याकांड के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि रेत के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

जिला खनिज अधिकारी इंद्र लाल राजवाड़े ने बताया कि विभाग को गेज नदी से अवैध रेत परिवहन की लगातार सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, जहां दो ट्रैक्टर और तीन टिपर मिले।

संक्षिप्त समाचार

रथयात्रा महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल डेका

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका रथ यात्रा



पर्व के अवसर पर गुरुवार को गायत्री नगर रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित महाप्रभु श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। राज्यपाल श्री डेका एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर 'छेरा-पहरा' की रस्म निभाई। राज्य की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी ने श्री जगन्नाथ जी की विधि-विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

रथयात्रा हमारी आस्था, संस्कृति और लोक परंपरा का जीवंत उत्सव : वित्त मंत्री

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने



भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथयात्रा के अवसर पर प्रदेशवासियों एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि सभी देशवासियों को रथयात्रा की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रथयात्रा हमारी भारतीय संस्कृति, आस्था और लोक परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है। भगवान श्री जगन्नाथ का जीवन समरसता, सेवा, करुणा और लोककल्याण का संदेश देता है, जो हमारे सामाजिक एवं सार्वजनिक जीवन के लिए सदैव प्रेरणास्त्रोत रहा है। श्री चौधरी ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि उनके गांव में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है और बचपन से ही वे गांववासियों के साथ रथयात्रा में सहभागी होते आए हैं। उन्होंने कहा कि यह परंपरा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने, सेवा, सहयोग और सामूहिक सहभागिता की भावना को मजबूत करने का माध्यम भी है। वित्त मंत्री ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा हमें समानता, सद्भाव और जनसेवा का संदेश देती है। उन्होंने कामना की कि भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का संचार हो तथा प्रदेश और देश निरंतर विकास एवं जनकल्याण के पथ पर अग्रसर रहे।

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का राजपत्र में हो चुका है प्रकाशन, जल्द होगा दूसरा स्टेप

रायपुर। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधेयक का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है, अब अब उसके नियमों का प्रकाशन भी होगा। एक स्टेप हो चुका है, अब दूसरा स्टेप जल्द होगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बस्तर में माओवाद वर्ग संघर्ष खड़ा नहीं कर पाया, लेकिन बस्तर के गांवों में धर्म संघर्ष खड़ा हो गया। जो काम माओवाद नहीं कर सका, वह धर्मांतरण ने कर दिया है। वहीं महादेव सट्टा एप मामले में विकास गर्ग की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा का अगर कोई व्यक्ति दिखेगा तो कठोर कार्रवाई होगी। महादेव सट्टा एप को कांग्रेस ने संरक्षण दिया था। राज्य सरकार इस मामले में काम कर रही है। बता दे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास गर्ग को भाजपा पदाधिकारी बताते हुए सरकार पर निशाना साधा था



नचनिया जलाशय के विकास कार्यों के लिए 3.91 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के तहत एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृति दी गई है। विभाग द्वारा खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के विकासखण्ड छुईखदान में स्थित नचनिया जलाशय के विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 3 करोड़ 91 लाख 26 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना से क्षेत्रीय किसानों को कुल 101 हेक्टेयर क्षेत्र में उन्नत सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। इस प्रशासनिक स्वीकृति के तहत नचनिया जलाशय के शीर्ष कार्य के साथ-साथ नहरों की रिमॉडलिंग और सीसी लाइनिंग (कंक्रीट लाइनिंग) का कार्य कराया जाएगा। इन कार्यों के पूरा होने से पानी के रिसाव में कमी आएगी और टेल एंड (अंतिम छोर) तक पानी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। जल संसाधन विभाग की इस योजना के प्रस्तावित कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपरांत क्षेत्र के कृषि परिदृश्य में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना से क्षेत्रीय किसानों को कुल 101 हेक्टेयर क्षेत्र में उन्नत सिंचाई सुविधा का प्रत्यक्ष लाभ मिलने लगेगा, जिससे फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी।

सदन में गूंजा मछुआ नीति के तहत गलत आबंटन, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा

सत्ता के जवाब से विपक्ष नाखुश, मंत्री नेताम ने सदन में की नई नीति में विसंगतियों को दूर करने की घोषणा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथे दिन मछुआ नीति को लेकर विपक्ष और पक्ष आमने सामने हुए।इसके साथ ही सदन में कामधेनू विश्वविद्यालय में गड़बड़ी और खाद के भंडारण को लेकर भी विपक्ष ने सरकार से सवाल किए।

विधानसभा में पहला प्रश्न कुंवर निषाद ने किया 25 लाख मछुआरा परिवार निवासरत है।जिसे लेकर कृषि मंत्री से सवाल पूछा गया था कि मछुआरा नीति के तहत पंजीयन और पट्टा आबंटन को लेकर प्रश्न किया। कुंवर सिंह निषाद ने प्रश्न किया कि वर्तमान प्रभाव से नीति के तहत समिति अथवा समूह में परिवार के एक ही सदस्य हो सकते हैं।राज्य शासन के विभिन्न अधिनियम और नियम के तहत पंजीयन मछुआ समिति और समूह पट्टा आबंटन हेतू पात्र होंगे। इस पर कुंवर सिंह निषाद ने सवाल किया कि क्या किसी सहकारी समितियों का निर्धारण सदस्यता संचालन वर्तमान नीति के तहत किया जाता है या छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम 1960 या उप नियमों के अनुसार सहकारी विभाग के द्वारा किया जाता है।

इस सवाल के जवाब में रामविचार नेताम ने कहा कि सदस्य ने जो जानकारी मांगी थी उसके बारे में हमने बिंदुवार जानकारी दी है।लेकिन जो उन्होंने प्रश्न किया है उसके विषय में मैं बताना चाहूंगा कि जो नीति है वो 2022 की नई नीति के मुताबिक ही प्रभावशील है।उसी नीति के तहत मछुआ समुदाय समिति और समूहों को पट्टा दिया गया है।

कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि जो नीति है उसके विरुद्ध जाकर जांजगीर में दो समूहों को पट्टा आबंटन किया गया है।कुंवर सिंह निषाद ने आरोप लगाए कि जिन परिवारों को पट्टा दिया गया है वो गैर मछुआ समाज से हैं।जिस परिवार को पट्टा दिया गया है वो अल्पसंख्यक है।जबकि जो मछुआ परिवार वहां पर 39 साल से है बलोदा मछुआ सहकारी समिति उसे पट्टा नहीं मिला है। जब उन्होंने मांग किया है तो हमारे समुदाय के 21 लोगों के ऊपर स्त्रङ्कक्र हुआ है। कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि जिन अधिकारियों ने गैर मछुआ समुदाय के लोगों को तालाब आबंटन किया है क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही नहीं जो पात्र हैं उनको फिर से पट्टा मिलेगा क्या।

इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जहां तक समितियों का सवाल है वो पूरी तरह से वैध हैं। जांच के प्रश्न पर मैं कहना चाहूंगा कि जो भी शिकायतें आईं थी उसका निराकरण संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया गया है,उसकी रिपोर्ट भी आई है।यदि इसके बाद भी सदस्य को लगता है कि जांच में विसंगतियां हैं तो हम उसके लिए जांच करेंगे।



लेकिन विधायक कुंवर निषाद ने कहा कि वो चाहते हैं विधानसभा की जांच समिति बने और उसमें उन्हें सदस्य बनाया जाए। निषाद ने आरोप लगाए कि जिसे पट्टा मिला है उसने स्वीकार किया है कि उसने निजी इस्तेमाल के लिए पट्टा लिया है। हैरानी की बात ये है कि ग्राम समिति यदि किसी आवेदन पर 6 महीने तक निर्णय नहीं लेती तो वो स्वत: ही निरस्त हो जाता है।लेकिन यहां तो 18 माह बाद पट्टा जारी हुआ है।इस बात को पट्टाधारी ने लिखित में दिया है।

निषाद के प्रश्न पर रामविचार नेताम ने कहा कि जिस प्रकरण की बात कह रहे हैं वो न्यायालय में भी था। हमारा विभाग किसी को भी तालाब आबंटित नहीं करता है। इस तालाब के अलावा भी अन्य तालाब उस जगह पर हैं।यदि आपको लगता है कि किसी समिति के साथ नाइंसाफी हुई है तो हम उस समिति को भी तालाब देंगे। साथ ही साथ जो भी विसंगतियां हुई हैं उस पर जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी।

वहीं इस बारे में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सवाल किया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन क्षेत्र में आने वाले तालाबों का अधिकार किसी अन्य विभाग के पास नहीं जा सकता।वो केवल वहां के रहने वालों के लिए ही है। लेकिन आपकी जो नीति है उसमें आपने लिखा है कि ये नीति वन क्षेत्रों में छोड़कर अन्य समस्त क्षेत्रों में लागू होगा। ये करने के बाद जो हमारे आदिवासी भाई वहां पर टेंडर ले रहे हैं वो इससे मुक्त हो जाएंगे।आप आदिवासी से ना पैसे ले सकते हैं, ना टेंडर दे सकते हैं।आप कुछ नहीं कर सकते हैं।आदिवासियों की जमीन पर जो जल क्षेत्र है वो आदिवासियों का है मुक्त का है।इसलिए मछुआ नीति 2022 में केवल एक लाइन का संशोधन करने की जरुरत है क्या आप करेंगे।

इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जिस नियम की बात नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं वो हमारा नहीं बनाया है।इन्हीं ने बनाया है।पिछली बार भी इन्होंने ये प्रश्न किया था। इस पर मैं जवाब देना चाहता हूं कि हम नई नीति ला रहे हैं।इस पर विभाग काफी गंभीर है और जो भी कमियां हैं उसको दूर की जाएंगी।

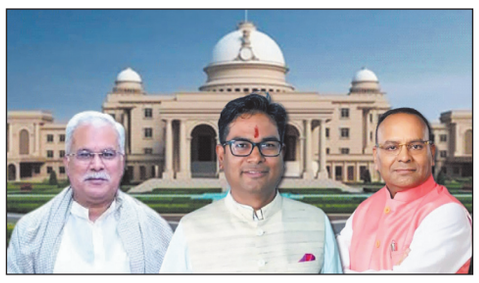
वहीं कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने उन जिलों में जहां पर खाद की डिमांड कम है और आपूर्ति ज्यादा की गई है इसे लेकर प्रश्न लगाया था। दलेश्वर साहू ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में खाद की डिमांड नहीं है।लेकिन वहां पर बिना मांगें भंडारण किया गया है। यही नहीं प्राइवेट खाद भंडारण ज्यादा है । आप अंदर से लेटर डालते हो कि इसको 48% और 52% विभाग उत्तर दिया है।इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि 13 जुलाई 2026 तक 14 लाख 6 हजार 555 मीट्रिक टन भंडारण है। जबकि 5 लाख 88 हजार मीट्रिक टन निजी क्षेत्र का भंडारण दिया गया है। बस्तर और सरगुजा के इलाके में खाद नहीं पहुंच पाता था। हम उस इलाके में ज्यादा खाद भेजे हैं। मैदानी इलाके में खाद की कोई दिक्कत नहीं होगी। खाद का पूरा भंडारण है। किस कंपनी को कितना खाद आना है यह केंद्र सरकार तय करती है। कौन सा रैक किस जगह पर जाएगा ये हमारी एजेंसी नहीं तय करती है। हम सिर्फ डिमांड ही भेजते हैं।आपूर्ति करने का काम केंद्र का होता है।

अजय चंद्राकर ने लोकधन के दुरुपयोग पर वित्तमंत्री चौधरी से मांगा जवाब

स्वेच्छाचारिता टिप्पणी पर चंद्राकर और बघेल आमने-सामने

रायपुर। विधानसभा में नवा रायपुर के सेवाग्राम परियोजना को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सेवाग्राम पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाने को लेकर सवाल उठाते हुए इसे एक व्यक्ति विशेष की स्वेच्छाचारिता का परिणाम बताया। इस टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन का माहौल गरमा गया।

विधानसभा में नवा रायपुर स्थित सेवाग्राम की वित्तीय और भौतिक स्थिति पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि सेवाग्राम बनाने का निर्णय 10 मार्च 2022 को लिया गया था। परियोजना का उद्देश्य महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर ग्राम की अवधारणा को साकार करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना



और कारीगरों को प्रशिक्षण देना है।

मंत्री ने बताया कि परियोजना के लिए वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कुल 129 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया। मल्टीपरपज डाइनिंग हॉल, सामुदायिक किचन और प्रसाधन कक्ष पर 3.72 करोड़ रुपये तथा अन्य निर्माण कार्यों पर 104.05 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सरकार के अनुसार सेवाग्राम के सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि इसके संचालन के लिए अभी तक कोई अलग सेटअप स्वीकृत नहीं किया गया है।

मंत्री के जवाब के बाद भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि एक व्यक्ति विशेष की स्वेच्छाचारिता की वजह से करीब 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। इस टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तत्काल खड़े हुए और कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इस बयान का विरोध करते हुए स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी टीका-टिप्पणी शुरू हो गई और सदन में कुछ देर तक जोरदार बहस का माहौल बना रहा।

अजय चंद्राकर ने बाद में स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को आहत करना नहीं था, और उन्होंने अपनी टिप्पणी से भूपेश बघेल की भावनाएं आहत होने पर सदन में खेद भी व्यक्त किया।

अलदा में फर्जी प्रस्तावों से उद्योग स्थापना और नामजद एफआईआर न होने पर सवाल

- मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉक आउट

रायपुर। विधानसभा में गुरुवार को फर्जी ग्रामसभा प्रस्तावों के आधार पर उद्योग स्थापना को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार से दोषियों पर कार्रवाई और कंपनियों को आवंटित जमीन निरस्त करने की मांग की। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

भूपेश बघेल ने ग्राम अल्दा और देवरी-घुलघुल में उद्योग स्थापना के लिए कथित फर्जी ग्रामसभा प्रस्तावों का मुद्दा उठाया।

सरकार ने बताया कि दोनों कंपनियों ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु अधिनियम के तहत सहमति के लिए आवेदन ही नहीं किया, इसलिए मंडल को ग्रामसभा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

सरकार ने स्वीकार किया कि ग्राम अल्दा के प्रस्ताव में जालसाजी की शिकायत की जांच त्रि-सदस्यीय समिति ने की थी। जांच में पाया गया कि ग्रामसभा ने सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने का प्रस्ताव पारित किया था, जबकि कार्यवाही पंजी की अंतिम दो पंक्तियां किसने लिखीं, इसकी



जानकारी किसी को नहीं है।

सरकार ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर 22 जून 2026 को थाना तिल्दा-नेवरा में बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने संबंधित परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की है।

भूपेश बघेल ने पूछा कि क्या सरपंच-सचिव पर कार्रवाई होगी? बालाजी स्पंज एवं आयरन लिमिटेड और अग्रसेन स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित जमीन निरस्त की जाएंगी। पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पुलिस विवेचना कर रही है, जांच के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों और कंपनियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया।

विधानसभा में उठा सेरीखेड़ी व अन्य आवासीय प्लॉट में सड़क निर्माण का मामला

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, नवा रायपुर एवं समीपस्थ क्षेत्र तथा सेरीखेड़ी में आवंटित आवासीय प्लाट में हाऊसिंग बोर्ड के द्वारा आवास भवन निर्माण एवं



आवासीय भवन हेतु आवंटित क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य का मामला विधानसभा में विधायक द्वारिकाधीश यादव ने उठाया। वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने बताया कि सेरीखेड़ी में एम.पी./एम.एल.ए./ ए.आई.एस. हेतु विशेष आवासीय योजना के तहत 134 भूखण्डों का सड़क निर्माण अनुबंधानुसार 08.07.2026 तक पूर्ण किया जाना है, परन्तु भूखण्ड का आबंटन नहीं होने से विकास कार्य हेतु स्ववित्तीय योजना के तहत पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता है, जिस कारण सड़क निर्माण अपूर्ण है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता है।

प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे सरोना और बालोद रेलवे स्टेशन का लोकार्पण

- सीएम साय ने कहा- रेलवे के आधुनिकीकरण से व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई गति

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के सरोना एवं बालोद रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, सुगम, सुरक्षित एवं यात्री-अनुकूल बनाकर देश की परिवहन व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से गुरुवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में रायपुर मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) दयानन्द ने सौजन्य



भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित सरोना एवं बालोद रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन समारोह के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आमंत्रण पत्र भेंट किया। भेंट के दौरान अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सरोना एवं बालोद रेलवे स्टेशनों पर विकसित आधुनिक यात्री सुविधाओं, अधोसंरचना उन्नयन तथा स्टेशनों के नए स्वरूप को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है, जिसका लाभ सीधे आम नागरिकों और प्रदेश के समग्र विकास को मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे आज अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। देशभर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर यात्री सेवाओं और विश्वस्तरीय अधोसंरचना से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को नई गति मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि विकास, व्यापार, पर्यटन और जनसुविधाओं की जीवनरेखा है। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरोना एवं बालोद रेलवे स्टेशनों के उन्नयन से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ में आधुनिक रेल अधोसंरचना का विस्तार तेजी से हो रहा है। रेल संपर्क के सुदृढ़ होने से प्रदेश में निवेश, उद्योग, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आम नागरिकों का आवागमन अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनेगा।

खरीफ सीजन में किसानों को मांग अनुसार दिया जा रहा डीजल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक अटल श्रीवास्तव के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने सदन को बताया कि वर्ष 2026-27 के खरीफ सीजन हेतु राज्य सरकार द्वारा 3 लाख मे.टन डी.ए.पी. की मांग आंकलित की गई, जिसके अनुरूप ही भारत सरकार द्वारा 3 लाख मे.टन डी.ए.पी. का आवंटन/लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में 01.04.2026 की बचत सहित कुल 1 लाख, 49 हजार, 874 मे. टन की आपूर्ति/भण्डारण कर 91 हजार, 991 मे.टन डी.ए.पी. का वितरण किया जा चुका है। प्रति एकड़ डी.ए.पी. उर्वरक की आवश्यकता का आंकलन फसल एवं मिट्टी परीक्षण परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। विगत वर्ष कृषक द्वारा उठाव किये गये



डी.ए.पी. उर्वरक की 60 प्रतिशत् मात्रा एवं शेष मात्रा वैकल्पिक उर्वरकों जैसे-एन.पी.के., एस.एस.पी. एवं नैनो डी.ए.पी. के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

श्रीवास्तव ने फिर पूछा कि क्या कृषि कार्यों एवं सिंचाई के लिये किसानों को डीजल की सुचारू उपलब्धता हो रही है? इस पर मंत्री नेताम ने बताया कि विभाग द्वारा कृषि कार्य हेतु डीजल की मांग का पृथक से आंकलन नहीं किया जाता है, अत: जिलेवार विवरण दिया जाना संभव नहीं है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ सीजन हेतु कृषि कार्यों एवं सिंचाई के लिये किसानों को डीजल सुचारू रूप से उपलब्ध हो रही है। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यक नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए किसानों को मांग अनुसार डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में राज्य में डी.ए.पी. की आपूर्ति और भण्डारण का कार्य लगातार प्रगति पर है ताकि मांग के अनुसार इसकी कमी न होने पाए। डीएपी उर्वरक एवं डीजल की कमी से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने हेतु किसानों को मांग अनुसार डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है तथा राज्य सरकार द्वारा डी.ए.पी. के विकल्प के रूप में किसानों को एन.पी.के., एस.एस.पी. आदि वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) धमतरी (छ.ग.)

E- mail- tribal.dhamtari@gmail.com, Phone no.- 07722-232142

कमांक / 2484 / आजाक / निर्माण / 2026 धमतरी, दिनांक 13/07/2026

-: मैनुअल पद्धति प्रथम निविदा आमंत्रण :-

एतद् द्वारा आदिम जाति विकास विभाग धमतरी अन्तर्गत विभागीय छात्रावास / आश्रमों में बोर खनन एवं सबमर्शिबल पंप स्थापना एवं पेयजल व्यवस्था तथा शौचालय स्नानागार निर्माण कार्यों के संपादन हेतु लोक निर्माण विभाग में जीवित पंजीयनयुक्त पंजीकृत सक्षम श्रेणी के ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के एस.ओ. आर दर जो दिनांक 01.01.2015 तथा विद्युतीकरण कार्य हेतु दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची निविदा आमंत्रण तिथि तक संशोधित दर अनुसूची पर निविदा प्रपत्र "अ" में प्रतिशत के आधार पर दर निम्नांकित कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक आमंत्रित की जाती है:-

01- निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	03/08/2026
02- निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	07/08/2026
03- निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि	10/08/2026
04- कार्य पूर्ण करने की तिथि	बोरवेल के लिए 01 माह शौचालय-स्नानागार 03 माह
05- निविदाकार की श्रेणी	डी वर्ग या उच्च
06- निविदा प्रपत्र का मूल्य	2000/- प्रति कार्य।

क्र	कार्य का प्रकार	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत राशि
01	02	03	04
01	विभागीय छात्रावासों / आश्रमों में नलकूप खनन एवं पेयजल व्यवस्था कार्य।	29	75.98 लाख
02	विभागीय छात्रावासों / आश्रमों में शौचालय-स्नानागार निर्माण कार्य	06	31.68 लाख

01- निविदा की शेष शर्तें एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, धमतरी के कार्यालय के सूचना बोर्ड में कार्यालयीन समयावधि में अवलोकन किया जा सकता है।
02- आदिवासी विकास धमतरी अन्तर्गत पूर्व में जारी कार्य आदेश के ऐसे ठेकेदार जिन्होने निर्माण/लघु निर्माण/अनुरक्षण / जीर्णोद्धार कार्यों को निर्धारित अवधि समाप्त होने के तीन माह बाद तक भी पूर्ण नहीं किया गया है, वे इस निविदा हेतु अपात्र होंगे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास धमतरी

जी-262702132/6

समस्या यह है कि क्षेत्रीय पार्टी टिकी नहीं रह पाती

वंदिता मिश्रा

प्रशांत किशोर बिहार में एक उपचुनाव लड़ेंगे, ताकि राजनीतिक जमीन का दावा किया जा सके। यह कदम उनकी नई पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में पैर जमाने में विफल रहने के महीनों बाद उठाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में, चुनावी करारी हार के बाद, ममता बनर्जी की टी.एम.सी. बिखर रही है। यू.पी. में, जहां अगले साल के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सत्ताधारी भाजपा के आंतरिक झगड़े समाजवादी पार्टी की तुलना में अधिक सुर्खियां बटोर रहे हैं, जो लगभग 2017 में सत्ता गंवाने के बाद से जनता की धारणा में निष्क्रिय है। ये छवियां हाल के समय की हैं-लंबे करियर वाले क्षेत्रीय दल/नेता शांत पड़े हैं, यहां तक कि जन सुराज जैसा नया दल, जो एक बिल्कुल नई शुरुआत के साथ आया था, उसे भी उसी अविश्वास का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय पार्टी भाजपा की आक्रामक राजनीति के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही है, जिसे उसके 'एक राष्ट्र' के सिद्धांत, एकरूपता की ओर बढने के प्रयास और खेल के मैदान को अपने पक्ष में मोडने के लिए डर और प्रलोभन के उपयोग का समर्थन प्राप्त है। संगठनात्मक मजबूती पर ध्यान न देने के कारण टी.एम.सी. ने अपनी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जगह राजनीतिक परामर्शदाता कंपनी आईपैक को सौंप दी। यह बदले में टी.एम.सी. के पुराने नेताओं द्वारा पार्टी छोडने के सिलसिले में योगदान दे रहा है। राष्ट्रीय पार्टियां भी इस क्षरण से प्रभावित हैं लेकिन क्षेत्रीय दलों की इसका सामना करने में असमर्थता अधिक स्पष्ट है। समस्या क्षेत्रीय दलों के अपने स्वयं के आत्मसमर्पण में भी निहित है, जो भाजपा के साथ उनके मुकाबले में अब उन्हें परेशान कर रही है। हाल ही में यू.पी. का दौरा करने पर इस बात से गहरा धक्का लगा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा, 9 साल से अधिक समय से सत्ता से बाहर होने के बावजूद, अभी भी अपनी पुरानी छवि की कैदी बनी हुई है। अखिलेश को अभी भी व्यापक रूप से परिवार से घिरे नेता के रूप में देखा जाता है, सपा को उस मुस्लिम-यादव पार्टी के रूप में देखा जाता है, जो सत्ता में रहने पर कानूनविहीनता की अध्यक्षता करती है। ये असाधारण समय है, जब भाजपा विपक्ष की राजनीति के लिए जगहों को सिकोड़ रही है। लेकिन अन्य क्षेत्रीय दलों की तरह, सपा इसके जवाब में एक असाधारण राजनीति पेश करने में असमर्थ रही है। यह सामान्य राजनीति के पैमाने पर भी कमतर साबित हुई है। इसने कोई नया राजनीतिक या आर्थिक मॉडल सामने नहीं रखा। जमीन पर, एम.वाई (मुस्लिम-यादव) से पी.डी.ए. (पिछड़ा, दलित, अनुसूचित जाति/अल्पसंख्यक) की राजनीति में इसके घोषित बदलाव को एक पुराने, बहिष्कृत जातिगत अंकगणित के रूप के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ है, जो एक स्तर पर व्यापक सामाजिक इंजीनियरिंग द्वारा इसे मात देता है और दूसरे स्तर पर 'सबका साथ...' का दावा करता है। भाजपा द्वारा तय नहीं की गई शर्तों पर भाजपा से लडने की असमर्थता, परिवार की राजनीति, एक जाति-एक समुदाय के जाल से बाहर निकलने में असमर्थता के अलावा, उन क्षेत्रीय दलों में आम है जो भाजपा के पक्ष में फीके पड़ते या उसकी ओर ड्क्षखचते हुए दिखाई दे रहे हैं।फिलहाल, भले ही भाजपा के प्रभुत्व में दरारें दिखाई देने लगी हैं, लेकिन जिन पार्टियों को राजनीतिक जगहों के खुलने से फायदा हो सकता था, वे दुर्भाग्य से इसके लिए तैयार नहीं हैं।

मोसाद ने ईरान के राष्ट्रपति को ही जासूस बना लिया?

अभिनय आकाश

कोई खुफिया एजेंसी कितनी दुस्साहसी हो सकती है? दुश्मन देश में जासूस भेज देगी। ऑपरेशन कर देगी, राज चुरा लेगी। इससे ज्यादा कुछ आपके दिमाग में आ रहा है क्या? लेकिन दुनिया में एक एजेंसी है जो हर बार ऐसा कुछ करती है कि गेम एक नए लेवल पर चला जाता है। हम मोसाद की बात कर रहे हैं। वही मोसाद जो पेजर में बम छुपा देती है और महीनों बाद उसे डेटोनेट करती है। अगले ही दिन वायरलेस सेट में धमाका करती है, उसका भी किसी को अंदेशा नहीं होता। लेकिन क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश का पूर्व राष्ट्रपति अपने ही दुश्मन देश का एजेंट बन जाए। ये कहानी ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की है। अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबरा द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये दावा किया है कि अहमदीनेजाद को इजरायल ने अपने जासूस की तरह इस्तेमाल किया। महमूद अहमदीनेजाद 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति थे। उस दौरान वो ईरान के सबसे कट्टर नेताओं में गिने जाते थे। जब वो राष्ट्रपति थे तो अक्सर इजरायल के खिलाफ बड़े बड़े बयान दिया करते थे। इजरायल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे। उन्हीं के शासनकाल में ईरान ने अपना यूरेनियम प्रोग्राम शुरू किया था। जिसके बाद दुनिया के कई देशों को शक हुआ कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। उस समय ऐसा लगता था कि उन्हें इजरायल से सबसे ज्यादा नफरत है। लेकिन ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद को लेकर अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है कि वही राष्ट्रपति पद से हटने के बाद से इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे थे। यानी वो मोसाद के एजेंट बन गए थे।

26 सितंबर 2016 ईरान के सुप्रीम लीडर आया अली खामनेई को तेहरान की एक इस्लामिक सेमिनरी से आमंत्रण आया। उस कार्यक्रम में उन्हें सेमिनरी के छात्रों को संबोधित करना था। कार्यक्रम में खामनेई जाते हैं। धर्म की बात करते हैं। साथ में उस समय ईरान की राजनीति के सबसे विवादित शख्स पर भी टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि अहमदीनेजाद मुझसे मिलने आए थे। मैंने उनसे अगला राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने की सलाह उनको दी है। अपील की है। अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो यह देश को दो हिस्सों में बांट सकता है। जिससे अंत में देश



का ही नुकसान होगा। ठीक 7 महीने बाद 20 अप्रैल 2017 को ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद राष्ट्रपति चुनाव का पर्चा भर देते हैं। बड़ी खबर यहां यह नहीं थी कि अहमदीनेजाद ने फिर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। बल्कि बड़ी खबर यह थी कि उन्होंने रहबर मुहज्जम इंकलाब इस्लामी यानी ईरान की इस्लामिक क्रांति के सुप्रीम लीडर की अवहेलना की। सार्वजनिक रूप से खामनेई के मना करने के बाद भी अहमदीनेजाद ने पर्चा भरा। लेकिन गार्डियन काउंसिल ने उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया। ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए गार्डियन काउंसिल का अप्रूवल मिलना जरूरी होता है। इसके लिए 12 मेंबर्स की सहमति आपको चाहिए होती है जो गार्डियन काउंसिल में बैठते हैं। छह सिविल लॉयर्स होते हैं जिनको पार्लियामेंट चुनती है वहां की और छह इस्लामिक धर्म गुरु होते हैं जिन्हें सीधे सुप्रीम लीडर चुनते हैं।

अहमदीनेजाद 2005 से 2013 यानी दो टर्म्स के लिए ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। चार-चार साल का वहां कार्यकाल होता है। ईरानी सिस्टम में एक शख्स दो टर्म्स तक राष्ट्रपति रह सकता है। इसके बाद उसे न्यूनतम एक साल का गैप देना होता है। लगातार तीन नहीं लड़ सकते। 2017 में जब अहमदीनेजाद पर्चा भरते हैं तो कानूनी रूप से सही थे। अगर उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी मिलती तो उनका सामना सर्विंग प्रेसिडेंट हसन रूहानी से होता। अब रूहानी जो थे अलोकप्रिय नहीं थे। रिजीम की ही पसंद के थे। लेकिन रूहानी और अहमदन एजाद के बीच अगर पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट होता तो कौन जीतता ईरान में हर कोई जानता था। इसके बाद अहमदीनेजाद 2021 में चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। जब रईसी जीतते थे। खामनेई की अनुमति उन्हें नहीं मिली। रईसी की असल में मृत्यु हो जाती है तो 2025 में फिर चुनाव होते हैं। तो एक बार फिर अहमदीनेजाद पर्चा भरना चाहते हैं। लेकिन रहबर साथ नहीं देते। यहां तक आते-आते अहमदन इजाज समझ जाते हैं कि खामनेई अपने जीते जी उन्हें प्रेसिडेंट बनने नहीं देंगे और अब अगर उन्हें सत्ता हासिल करनी है तो कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा।

मोसाद के इस ऑपरेशन की शुरुआत साल 2022 के आसपास हुई। मोसाद को लग रहा था कि अहमदीनेजाद ईरानी सत्ता से नाराज है और दोबारा देश की कमान संभालना चाहते हैं। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइली अधिकारियों का मानना था कि अहमदीनेजाद की ईरान के कामकाजी और कम कमाई वाले लोगों के बीच अब भी पकड़ है। ऊपर से वह ईरान के पुराने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का जाना माना चेहरा भी थे। ऐसे में अगर ईरान की मौजूदा सत्ता गिरती तो उन्हें नए नेता के तौर पर सामने लाया जा सकता था। यह अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाली एक योजना थी। जिस नेता ने खुद के राष्ट्रपति रहते हुए इजराइल को कभी मुंह नहीं लगाया, उसी नेता को इजराइल अपना एजेंट बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मोसाद का मकसद सिर्फ खुफिया जानकारी हासिल करना नहीं था। क्योंकि खुफिया जानकारी के लिए मोसाद इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। उसका असली मकसद ईरान की गद्दी पर अहमदीनेजाद को बैठाना था। अब मोसाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अहमदीनेजाद से बात कैसे हो और उसके लिए मुनासिब जगह क्या होगी? इसके लिए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट को चुना गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 की शुरुआत में हंगरी सरकार के एक आला अधिकारी ने लुडोविका यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक सर्विस के रेक्टर गिरगली डेली से संपर्क किया। उनसे क्लाइमेट चेंज पर एक कॉन्फ्रेंस करने और उसमें अहमदीनेजाद को बुलाने के लिए कहा गया। लेकिन यह कॉन्फ्रेंस केवल एक दिखावा था। असली मकसद था अहमदीनेजाद और इजराइली खुफिया अधिकारियों के बीच सीक्रेट मीटिंग करवाना। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के तत्कालीन चीफ डेविड बर्निया खुद अहमदीनेजाद से मिलने बुडापेस्ट पहुंचे। दावा है कि अहमदीनेजाद के स्पोक्सपर्सन और करीबी इलाय अली अकबर जवनफेकर को इजराइल की ओर से कई अंडर दी टेबल पेमेंट्स भी किए गए। इजराइली अफसरों ने अहमदीनेजाद की ट्रिप्स और स्टे का खर्च तक उठाया। इसके बाद उनके खेमे और मोसाद के अफसरों के बीच और भी कई मुलाकातें हुई।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अहमदीनेजाद ने पिछले कुछ सालों में अपनी पुरानी कट्टर छवि को बदलने की भी कोशिश की। उन्होंने अंग्रेजी सीखी, अपने पहनावे और पब्लिक इमेज में बदलाव किया। यहां तक कि ईरानी सत्ता की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना भी शुरू किया। इजराइली खुफिया अधिकारियों को कथित तौर पर यह लग रहा था कि इस इमेज के साथ अहमदीनेजाद को आगे चलकर ईरान के एक नए लीडर के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन इस कहानी में सबसे ड्रामेटिक फेस फरवरी 2026 में आया। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदीनेजाद के घर के प्रेमाइसेस पर इजराइली हवाई हमला हुआ। इसमें उनके सुरक्षाकर्मियों और बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया गया। इसके बाद मोसाद के एजेंट कथित तौर पर अहमदीनेजाद को वहां से निकालकर तेहरान के एक सीक्रेट लोकेशन पर ले गए। लेकिन इसके बाद सब कुछ उतना स्मूथ नहीं रहा जैसा पहले था। दावा है कि अहमदीनेजाद इस पूरी कार्यवाही और युद्ध से नाराज हो गए थे। वे कुछ समय बाद उस सीक्रेट लोकेशन से बाहर निकल गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने चार सीनियर ईरानी अफसरों के हवाले से दावा किया गया कि इसके बाद ईरानी आलाकमान को अहमदीनेजाद के इजराइल से नजदीकियों की भनक लग गई थी। जिसके बाद आईआरजीसी की इंटेलिजेंस ब्रांच ने उन्हें हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया।

13 जुलाई को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामनेई के साथ विवाद के बाद अहमदीनेजाद अपने विश्वास पात्रों और सलाहकारों से विदेशी मदद के जरिए सत्ता हासिल करने पर बात करते थे। यह बात अखबार को अहमदीनेजाद के ही एक करीबी सहयोगी ने बताई है। अखबार ने एक डिटेल रिपोर्ट छापी जिसका टाइटल है इनसाइड इजराइल सीक्रेट ऑपरेशन टू कल्टीवेट अहमदीनेजाद। इसे मार्क मज़िटी, जुलनी बांस, फरनास फसीही और रन बर्गमन ने मिलकर लिखा है। इसमें दावा किया गया है कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो उनका लक्ष्य केवल इस्लामिक रिजीम को खत्म करना नहीं था।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)



(गतांक से आगे...)

उसका पहिला व्याह 40 वर्ष की अवस्था में हुआ था। वर्तमान स्त्री उसकी तीसरी स्त्री है जिसकी उम्र 70 वर्ष की है। सुधीखाँ अभी भी 5-6 माइल पैदल चल सकता है और 10-15 सेर चीज मजे में ले जा सकता है।

[ता0 1-11-25 के दैनिक भारत-मित्र कलकत्ता से -]

(2) संसार में हाजी ताहुर नाम का एक आदमी अभी तक है कि जिसने नेपोलियन को अपने जीवन में देखा। इसकी जन्मभूमि मवमाश्रजमल है। यह आधुनिक संसार के मनुष्यों में सबसे अधिक उम्र वाला है। क्योंकि यह स्वयं अपनी आयु 140 की बतलाता है।

इतना वृद्ध होने पर भी यह इतना हट्टा कट्टा है कि अपने तीसरे बार के जमे हुवे दांतों से कड़ी से कड़ी वस्तु को भी चाब सकता है। [ता0 6 जौलाई सन् 1626 के हिन्दू-सर्वस्व से -]

(3) बिलगुडर (सविया) में नमफीईरए फन्दी नामक एक बूढ़ा ऐसा है कि जिसने अपनी 151 वर्ष की अवस्था में 27 विवाह करके 110 बच्चे उत्पन्न किये हैं। [ता0 3-1-26 के भारत मित्र से-] (4) मनुष्य की आयु का निश्चय करना और उसके लिये सीमा बाँध देना असम्भव जान पड़ता है। पीटर मफेंस ने भारत के इतिहास में लिखा है कि नुमीसडे सन् 1566 में मरा, उस समय उसकी अवस्था 171 वर्ष की थी। टामसडार की आयु 152 वर्ष की थी । इफिन्धम 144 वर्ष की उमर में मरा। गुसांई लक्ष्मणपुरी इमलहा (मिर्जापुर)

116 वर्ष के हो कर मरे। [देशदर्शन पृ0 66 से] (5) वर्न गांव भुसावल में एक दर्शनीय परमहंस महात्मा ऐसे हैं कि जिनकी श्रायु इस समय तीन सौ वर्ष की है। [ता0 2-11-25 के हिन्दू-सर्वस्व से-]

क्रमशः ...

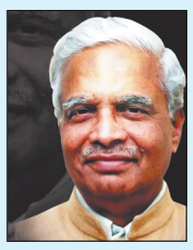
अखिल विद्यार्थी परिषद के आधार स्तंभ थे बाल आपटे

डॉ. राकेश मिश्रा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन में रीढ़ की भूमिका निभाने वाले बलवंत परशुराम (बाल) आपटे का जन्म 18 जनवरी, 1939 को पुणे के पास क्रांतिवीर राजगुरु के जन्म से धन्य होने वाले राजगुरुनगर में हुआ था।

उनके पिता श्री परशुराम आपटे एक स्वाधीनता सेनानी तथा समाजसेवी थे। वहां पर ग्राम पंचायत, सहकारी बैंक आदि उनके प्रयास से ही प्रारम्भ हुए। यह गुण उनके पुत्र बलवंत में भी आये। बालपन से ही संघ के स्वयंसेवक रहे बलवंत आपटे प्रारम्भिक शिक्षा गांव में पूरी कर उच्च शिक्षा के लिए मुंबई आये और एल.एल.एम कर मुंबई के विधि महाविद्यालय में ही प्राध्यापक हो गये।

1960 के दशक में विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद लगभग 40 वर्ष तक उन्होंने यशवंतराव केलकर के साथ परिषद को दृढ़ संगठनात्मक और वैचारिक आधार दिया। विद्यार्थी परिषद ने न केवल अपने, अपितु संघ परिवार की कई बड़ी संस्थाओं तथा संगठनों के लिए भी कार्यकर्ता तैयार किये हैं। इसमें आपटे जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।



1974 में विद्यार्थी परिषद के रजत जयंती वर्ष में वे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गये। इस समय महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश में युवा शक्ति सड़कों पर उतर रही थी। इस आंदोलन को विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रव्यापी बनाया। जयप्रकाश नारायण द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने से यह आंदोलन और अधिक शक्तिशाली हो गया।

इससे बौखलाकर इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। आपटे जी भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन करने लगे। दिसम्बर 1975 में वे पकड़े गये और मीसा नामक काले कानून के अन्तर्गत जेल में ठूंस दिये गये, जहां से फिर 1977 में चुनाव की घोषणा के बाद ही वे बाहर आये। जेल जीवन के कारण उनकी नौकरी छूट गयी। अत: वे वकालत करने लगे। अगले 20 साल तक वे गृहस्थ जीवन, वकालत और विद्यार्थी परिषद के काम में संतुलन बनाकर चलते रहे। उन्होंने संगठन के बारे में केवल भाषण नहीं दिये। वे इसके जीवंत स्वरूप थे।

1996 से 98 तक वे महाराष्ट्र शासन के अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे। जब उन्हें भाजपा में जिम्मेदारी देकर राज्यसभा में भेजने की चर्चा चली, तो उन्होंने पहले संघ के वरिष्ठजनों से बात करने को कहा। इसके बाद वे आठ वर्ष तक भाजपा के उपाध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के सदस्य तथा 12 वर्ष तक महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य रहे।

सांसदों को अपने क्षेत्र में काम के लिए बड़ी राशि मिलती है। उसकी दलाली का धंधा अनेक सांसद करते रहे। प्रारम्भ में कई लोग आपटे जी के पास भी इस हेतु से आये; पर निराश होकर लौट गये। लोग अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद वर्षों तक दिल्ली में मिले भवनों में अवैध रूप से डटे रहते हैं; पर आपटे जी ने कार्यकाल पूरा होने के दूसरे दिन ही मकान छोड़ दिया।

जीवन में अंतिम एक-दो वर्ष में वे अचानक कई रोगों से एक साथ घिर गये, जिसमें श्वांस रोग प्रमुख था। समुचित इलाज के बाद भी 17 जुलाई, 2012 को उनका मुंबई में ही देहांत हुआ।

हसीना की वापसी का दांव : आत्मसमर्पण या राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक

महेंद्र वेद

शेख हसीना का दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और आत्मसमर्पण करने का एलान एक बड़ा राजनीतिक दांव है, जिससे ढाका के अधिकारियों के पास कोई बेहतर विकल्प नहीं बचता। ऐसा करके वह एक भगोड़ी नेता की छवि से परे ऐसी नेता के रूप में सामने आती हैं, जो कानून और न्याय का सामना करने के लिए तैयार है। इससे उनके विरोधियों तथा सरकार पर राजनीतिक और नैतिक दबाव आ जाएगा और इससे ढाका का प्रत्यर्पण अभियान कमजोर पड़ जाएगा। साथ ही, उनका मुकदमा मौजूदा सरकार की वैधता की परीक्षा जैसा बन सकता है।

यह कदम उनकी प्रतिबंधित पार्टी अवामी लीग में भी नई जान फूंक सकता है। इससे सरकार दुविधा में पड़ सकती है कि या तो वह उन्हें शहीद जैसी छवि हासिल करने का मौका दे, या फिर न्यायपालिका पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने के आरोप झेले। जब बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथ का प्रभाव बढ़ रहा है, ऐसे में उनकी वापसी से देश में ज्यादा अशांति पैदा हो सकती है। पहले से ही मौजूद राजनीतिक ध्रुवीकरण गहराने की आशंका भी बनी हुई है।

रॉयटर्स के अनुसार, शेख हसीना का कहना है कि यह पूरी तरह उनका निजी फैसला है और इसमें किसी विदेशी सरकार की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि, इसके पीछे कई कारण दिखाई देते हैं। पहला, बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की सरकार को सत्ता में आए कई महीने हो चुके हैं। जुलाई-अगस्त 2024 के विद्रोह के बाद जो क्रांतिकारी उत्साह दिखाई दिया था, उसकी जगह अब कानून-व्यवस्था, महंगाई, रोजगार और आर्थिक सुधार जैसी रोजमर्रा की चुनौतियों ने ले ली है। दूसरा, लंबे समय तक देश से बाहर रहने के कारण उनकी पार्टी अवामी लीग के राजनीतिक रूप से खत्म होने का खतरा बढ़ गया है।



शेख हसीना इसी मनोवैज्ञानिक गिरावट को पलटना चाहती हैं। तीसरा, ऐसा लगता है कि वह राजनीतिक नियंत्रण को फिर से अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही हैं।

दरअसल, ऐसा करके वह एक साथ कई लोगों को संदेश दे रही हैं। अपने समर्थकों से वह कहती हैं 'मैंने आपको छोड़ा नहीं है।' बीएनपी सरकार के लिए उनकी चुनौती साफ है कि अगर आप मुझे जेल भेजते हैं या फांसी देते हैं, तो उसके नतीजों की जिम्मेदारी आपकी होगी। शेख हसीना की वापसी यह सवाल भी खड़ा करती है कि यदि राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो क्या सेना पूरी तरह तटस्थ रह पाएगी? वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपील कर रही हैं कि वे उनके खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई पर बारीकी से नजर रखें। हसीना ने खुद कहा है कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है या उनकी हत्या हो सकती है। उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और यदि अदालत उन्हें दोषी ठहराती है, तो मौत की सजा तक की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेशी लोग भावुक होते हैं, पर यह भी सच है कि हसीना की जान लेने की कई कोशिशें भी हुईं। ऐसे में, यदि वह देश लौटती हैं, तो कई जगहों पर हिंसा और राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।

रणनीतिक तौर पर, भारत के पास किसी भी तरह से इसमें शामिल न होने की वजहें हैं। लेकिन, इसमें कोई शक नहीं कि उनके जाने से रिश्ते सामान्य होने में मदद मिलेगी। भारत में उनकी मौजूदगी दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ी अड़चन रही है। हालांकि, नई दिल्ली ने बीएनपी सरकार के साथ कामकाजी रिश्ते फिर से मजबूत करने की कोशिश की है। भारत का मानना है कि ढाका में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, दोनों देशों के बीच संवाद जारी रहना जरूरी है। ऐसे में, यदि भारत को हसीना की वापसी में सक्रिय भूमिका निभाते हुए देखा गया, तो दोनों देशों के बीच बन रहे कूटनीतिक भरोसे को नुकसान पहुंच सकता है। भारत की प्राथमिकता यह होगी कि वह बीएनपी सरकार से बातचीत जारी रखे और कानूनी व कूटनीतिक माध्यमों से अवामी लीग के नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुपचाप कोशिश करे। भौगोलिक और रणनीतिक वास्तविकताएं दोनों सरकारों को वैचारिक मतभेदों के बावजूद व्यावहारिक सहयोग के लिए मजबूर करती हैं। हालांकि, भारत की यह रणनीति पूरी तरह सफल होगी, इसकी संभावना कम ही है।

मोदी सरकार पर 1971 के दौर जैसी कोई ऐतिहासिक जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसके सामने अपनी अलग चुनौतियां हैं। भारत के लिए देश में अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध लोगों, पूर्वोत्तर की सुरक्षा और बढ़ती भारत-विरोधी बयानबाजी चिंताजनक है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के नागरिकों की बढ़ती आवाजाही और हाल के दिनों में चीन के साथ बुनियादी ढांचे तथा कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर हुई बातचीत ने भारत की रणनीतिक चिंताओं को और बढ़ा दिया है। ऐसे में, दोनों देशों के रिश्ते धीरे-धीरे सामान्य हो सकते हैं, लेकिन शेख हसीना के कार्यकाल जैसा करीबी संबंध कायम होने की संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है।

अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि शेख हसीना की वापसी और उनकी पार्टी की जमीनी मौजूदगी, बांग्लादेश की पहले से जटिल राजनीतिक स्थिति को कितना और उलझाएगी। आने वाले समय में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अवामी लीग को कानूनी पाबंदियों के बावजूद फिर से राजनीतिक पहचान मिल सकती है। वहीं, हसीना के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इसे लेकर बीएनपी सरकार पर वैश्विक दबाव भी बढ़ सकता है। साथ ही, न्यायपालिका राजनीतिक घटनाक्रम का केंद्र बन सकती है, क्योंकि हसीना के खिलाफ चलने वाली कार्रवाई केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक महत्व भी रखेगी।

कुल मिलाकर, शेख हसीना की इस घोषणा का उद्देश्य तुरंत सत्ता में लौटना नहीं लगता। शायद, वह अपनी पार्टी को बांग्लादेश की राजनीति से हाशिये पर जाने से बचाने और उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी वापसी उन्हें सार्वजनिक जीवन से विदा लेने से पहले एक आरोपी के रूप में स्थापित करेगी या फिर वह एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति को दो ध्रुवों में बांट देने वाला सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगी। इसका जवाब काफी हद तक बीएनपी सरकार, अदालतों और खुद शेख हसीना के आगे के कदमों पर निर्भर करेगा।

आज का इतिहास

1906 क्लेमेंट आर्मंड फैलिएरेस फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए।
1912 अंतरराष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ (आईएएफ) की स्वीडन में स्थापना की गयी।
1916 अब्राहम लिंकन की जन्मस्थली को राष्ट्रीय ऐतिहासिक पार्क के रूप में लॉरॉय काउंटी के केंटकी शहर में स्थापित किया गया।
1918 रूसी क्रांति-बोल्शेविकों ने येकातेरिनबर्ग में ज़ार निकोलस द्वितीय और इस परिवार को निष्पादित किया।
1919 फिनलैंड में संविधान को अंगीकार किया गया।
1929 सोवियत संघ ने चीन के साथ राजनयिक संबंध समाप्त किए।
1936 राष्ट्रवादी विद्रोहियों ने दूसरे स्पेनिश गणराज्य के खिलाफ तख्तापलट का प्रयास किया, जिससे स्पैनिश गृह युद्ध छिड़ गया।
1944 अमेरिका में कैलिफोर्निया के समीप में गोला बारूद से लदे दो जहाजों में विस्फोट होने से 322 लोगों की मौत हो गयी।
1945 जोसेफ स्टालिन, विंस्टन चर्चिल और हैरी एस। ट्रूमैन, सोवियत संघ के नेता, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता, पोप्सडैम में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ क्या किया जाना चाहिए, यह तय करने के लिए मिले।
1950 दक्षिण अफ्रीका में साम्यवाद अधिनियम लागू किया गया।
1968 अहमद हसन अल-बक्र द्वारा निर्मित, अरब सोशलिस्टबाथ पार्टी ने इराकी राष्ट्रपति अब्दुल रहमान आरिफ को उखाड़ फेंका।
1973 अफ़ग़ानिस्तान के अंतिम राजा मोहम्मद ज़हीर शाह को उनके चचेरे भाई मोहम्मद दाउद खान ने तख्तापलट कर दिया था जबकि इटली में उनकी सर्जरी हुई थी।
1974 लंदन टॉवर में हुए बम धमाके से 41 लोग घायल हो गए।
1981 अमेरिका के मिसौरी के कैनसस सिटी के हयात रीजेंसीहोटल में एक संरचनात्मक असफलता के कारण एक पैदल मार्ग गिर गया, जिसमें से (क्षति का चित्रण) 114 लोगों की मौत हो गई और 216 अन्य घायल हो गए।
1992 महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने आधिकारिक तौर पर मैनचेस्टर मेट्रोलिंक, ग्रेटर मैनचेस्टर, इंग्लैंड में एक हल्की रेल प्रणाली खोली।
1994 धूमकेतू शुमेकर लेवी-9 का पहला टुकड़ा बृहस्पति से टकराया।
1995 नास्डैक कम्पोजिट इंडेक्स पहली बार 1,000 अंक से ऊपर बंद हुआ।
2009 दो आत्मघाती हमलावरों ने इंडोनेशिया के दो अलग-अलग होटल जकार्ता में खुद को विस्फोटित कर लिया।

पंजाब कांग्रेस में आपसी खींचतान : भाजपा ने मोदी को आगे कर पलट दी बाजी

नीरज कुमार दुबे

पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले का राजनीतिक परिदृश्य बड़ा हैरान कर देने वाला है। एक ओर सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी अपनी नाकामियों और तमाम तरह के आरोपों का सामना कर रही है, वहीं खुद को सत्ता की प्रबल दावेदार मान रही कांग्रेस में एकाएक जबरदस्त आपसी खींचतान मच गयी है। साथ ही पंजाब में कई बार राज कर चुका शिरोमणि अकाली दल अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है तो वहीं राज्य में पहली बार अपने दम पर सभी विधानसभा सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी भाजपा ने मौका देख कर अपनी चुनावी रणनीति को नई धार दे दी है।

हम आपको बता दें कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर विकास, धार्मिक-सामाजिक समीकरणों और नए राजनीतिक संदेश के सहारे अपनी जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जालंधर दौरे पर आ रहे हैं। उनका दौरा केवल विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे 2027 की चुनावी बिसात का स्पष्ट राजनीतिक संदेश छिपा है।

भाजपा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब राज्य की राजनीति सतलुज फिल्म विवाद से गर्माई हुई है। इस पूरे विवाद में भाजपा सबसे अधिक राजनीतिक दबाव में दिखाई दी। पार्टी लगातार यह कहती रही कि फिल्म को ओटीटी मंच से हटाने में उसकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन विपक्ष ने पूरे विवाद का राजनीतिक ठीकरा भाजपा पर ही फोड़ दिया। भाजपा के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आए। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने फिल्म को पंजाब की त्रासदी का एकतरफा चित्रण बताते हुए इसकी आलोचना की और कहा कि इसमें आतंकवाद की पृष्ठभूमि तथा पुलिसकर्मियों के बलिदान की अनदेखी की गई है। दूसरी ओर वरिष्ठ भाजपा नेता इकबाल सिंह लालपुरा ने सार्वजनिक रूप से बिट्टू को अपनी सीमाओं में रहने की सलाह दी। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने भी माहौल शांत करने की अपील करते हुए कहा कि पंजाब ने बहुत खून-खराबा देखा है, इसलिए पुराने जख्मों को कुरेदने की बजाय शांति और जिम्मेदार संवाद की जरूरत है। पार्टी के भीतर यह स्वीकार किया जा रहा है कि फिल्म कांग्रेस शासनकाल की घटनाओं पर आधारित होने के बावजूद



राजनीतिक जवाब भाजपा को देना पड़ रहा है।

ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी का विकास एजेंडा भाजपा के लिए राजनीतिक नैरेटिव बदलने का प्रयास माना जा रहा है। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का उद्घाटन, मोहाली, श्री मुक्तसर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब समेत कई रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण केवल आधारभूत ढांचे का विस्तार नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है कि भाजपा पंजाब में विकास की राजनीति को केंद्र में रखना चाहती है। साथ ही यह भी तय माना जा रहा है कि भाजपा पंजाब में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी।

इस दौरे का दूसरा बड़ा आयाम रविदासिया समाज तक पहुंच बनाना है। प्रधानमंत्री इससे पहले भी गुरु रविदास जयंती पर डेरा सचखंड बल्लां पहुंच चुके हैं। जालंधर और पूरा दोआबा क्षेत्र रविदासिया समुदाय का प्रभावशाली राजनीतिक केंद्र माना जाता है, जहां अनुसूचित जाति मतदाता चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनंदपुर साहिब और मोहाली जैसे धार्मिक एवं शहरी क्षेत्रों को भी इस दौरे में शामिल करना भाजपा की व्यापक सामाजिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। श्री मुक्तसर साहिब का चयन भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का गृह जिला है। हम आपको बता दें कि भाजपा पहले ही 2027 का चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है, हालांकि उसने गठबंधन के विकल्प पूरी तरह बंद भी नहीं किए हैं। ऐसे में विकास और सामाजिक आउटरीच के जरिए पार्टी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

दूसरी ओर कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि उसका अपना संगठन बन गया है। लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी के बावजूद पार्टी हाईकमान ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। पार्टी का आकलन है कि विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन संगठन को कमजोर कर सकता है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि राज्य के 29 में से 25 जिला अध्यक्ष, सात में से चार सांसद और 18 में से 10 विधायक वड़िंग के साथ हैं। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने भी स्पष्ट संकेत दिया कि फिलहाल यथास्थिति ही बनी रहेगी और मीडिया में चल रही अटकलों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

हालांकि यह फैसला कांग्रेस के भीतर नई खींचतान का कारण बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाकर शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन चन्नी समर्थक इसे पर्याप्त नहीं मानते। उनका तर्क है कि चुनाव अभियान का नेतृत्व करने और पंजाब में पार्टी का प्रमुख चेहरा बनने के बाद चन्नी को अधिक अधिकार मिलने चाहिए थे। वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई नेता भी वड़िंग के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि लोकतांत्रिक दल में मतभेद स्वाभाविक हैं और समय आने पर असंतुष्ट नेताओं को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन फिलहाल संगठन में स्थिरता सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

बहरहाल, स्पष्ट है कि पंजाब की राजनीति अब केवल विकास बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं रह गई है। भाजपा अतीत की बहसों से निकलकर विकास, रेलवे परियोजनाओं और रविदासिया समाज के जरिए नया राजनीतिक विमर्श गढ़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस अपने ही संगठनात्मक संकट से जूझते हुए एकजुटता बचाने में लगी है। इस बीच, सतलुज विवाद ने पंजाब के पुराने जख्मों को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है, लेकिन असली मुकाबला इस बात का होगा कि 2027 तक कौन-सी पार्टी जनता के सामने सबसे विश्वसनीय राजनीतिक कथा स्थापित कर पाती है। फिलहाल भाजपा विकास और सामाजिक समीकरणों के सहारे नई जमीन तलाश रही है, जबकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी परीक्षा अपने घर की कलह पर नियंत्रण पाने की है। पंजाब की चुनावी बिसात बिछ चुकी है और आने वाले महीनों में यही दोनों ध्रुव राज्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ती नाराजगी को देखते हुए सत्ता से उसकी विदाई तय मानी जा रही है।

युद्धोन्मादियों की बंधक न बने विश्व व्यवस्था? ईरानी नेतृत्व को सनकी मानते हैं ट्रम्प?

राजकुमार सिंह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरानी नेतृत्व को सनकी मानते हैं। ट्रम्प के बारे में भी शेष विश्व की कमोबेश यही राय है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की छवि भी ऐसी ही है। दरअसल ये तीनों ही मिल कर शेष विश्व की व्यवस्था को ही अपनी सनक का बंधक बनाते दिख रहे हैं। युद्ध विराम के बीच भी तनातनी के बावजूद जिस तरह अमेरिका और ईरान में 60 दिन का शांति समझौता हुआ तथा उसे स्थायी बनाने को लेकर बातचीत शुरू हुई। उससे विश्व व्यवस्था बहाल होने की उम्मीद जगी थी। लेकिन अचानक फिर एक-दूसरे पर हमले शुरू हो गए हैं। युद्ध के लिए किसी एक पक्ष को दोषी ठहराना आसान नहीं। लेकिन कोई कम दोषी होता है। तो कोई ज्यादा। चाहे 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी-इजराइली हमलों से युद्ध की शुरूआत हो या फिर अब शांति समझौता तोड़ कर फिर युद्ध। अमेरिका और खासकर उसके बड़बोले राष्ट्रपति ट्रम्प मुख्य खलनायक नजर आते हैं। अक्सर संवाद के जरिये समस्या के समाधान का रास्ता बंद हो जाने पर ही संघर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले तब शुरू किए। जब पहले दौर में कुछ मुद्दों पर सहमति के बाद वार्ता का दूसरा दौर तय हो गया था। आप सोच सकते हैं कि युद्ध कोई खेल नहीं। जिसे मनमाफिक समझौते के लिए दांव-पेंच की तरह इस्तेमाल किया जाए। पर महाशक्तियों के लिए तो युद्ध खेल भी है और मुनाफे का कारोबार भी। बेशक इस युद्ध में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अमेरिकी रक्षा हथियार निर्माता कंपनियों और तेल कंपनियों के तो बल्ले-बल्ले हैं। युद्ध होगा तो हथियार भी बिकेंगे ही। फिर अमेरिका तो कुछ छोटे



देशों की सुरक्षा का ठेकेदार बन कर भी मोटी रकम वसूलता है। मूलत: मुनाफाखोर कारोबारी ट्रम्प ने खुद माना कि जब विश्व ऊर्जा खपत के 20-22 प्रतिशत हिस्से के आयात का मार्ग होरमुज बंद था। तब अमेरिका ने भारी मात्रा में चोरी-छिपे तेल वहां से निकाला। नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का एजेंडा भी किसी से छिपा नहीं है। ईरान के कट्टरपंथी नेतृत्व के मंसूबे भी विश्व शांति के तो हरगिज नहीं। यह आईने की तरह साफ हो गया है कि तीनों ही संबंधित पक्ष अपने-अपने निहित स्वार्थों में उलझे हैं। उनका न विश्व शांति से कोई सरोकार है और न ही न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था से। इसलिए समय और समझ। दोनों का तकाजा है कि विश्व व्यवस्था को इनका बंधक बनने से बचाने के लिए शेष विश्व एकजुट होकर मुखर हो। बेशक कुछ छोटे देशों ने इस युद्धोन्माद के बीच शांति-समझौता वार्ताओं की पहल की। लेकिन शायद वे कोई नैतिक या कूटनीतिक दबाव बनाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए अब भारत। चीन। रूस। फ्रांस। जर्मनी जैसे देशों को समान विचारवाले अन्य देशों के साथ मिल कर अमेरिका-इजराइल-ईरान पर यह दबाव बनाना चाहिए कि वे संवाद के जरिये आपसी विवादों का मनमाना नहीं। तर्कसम्मत और न्यायपूर्ण समाधान निकालें। क्योंकि उनके अपने निहित स्वार्थों और सनक के लिए शेष विश्व की शांति और अर्थव्यवस्था को बंधक बनने नहीं दिया जा सकता।

राम के मंदिर में पारदर्शिता की अग्निपरीक्षा

कुमार कृष्णन

अयोध्या का श्रीराम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है। यह करोड़ों भारतीयों की आस्था, पांच शताब्दियों से अधिक लंबे संघर्ष, सामाजिक आंदोलनों और सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद साकार हुए राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। देश के कोने-कोने से लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार इस मंदिर के निर्माण में आर्थिक सहयोग दिया। किसी ने सौ रुपये दिए, किसी ने अपनी जीवन भर की बचत, तो किसी ने सोना-चांदी और बहुमूल्य धातुएं अर्पित कीं। इसलिए राम मंदिर से जुड़ा हर प्रश्न केवल एक ट्रस्ट या संस्थान का प्रश्न नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का प्रश्न है। यही कारण है कि मंदिर के चढ़ावे और दान में कथित अनियमितताओं का मामला जब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, तो इसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जवाब मांगा है। साथ ही उत्तर प्रदेश की विशेष जांच टीम (एसआईटी) से जांच की स्थिति रिपोर्ट भी तलब की गई है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि भी निर्धारित कर दी है। न्यायालय का यह कदम किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आरोपों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो तथा सत्य सामने आए। लोकतंत्र में न्यायपालिका की यही भूमिका है—विश्वास बनाए रखना और कानून के शासन को मजबूत करना।याचिकाओं में आरोप लगाए गए हैं कि मंदिर में प्राप्त दान और चढ़ावे के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। कुछ कर्मचारियों पर चढ़ावे में कथित गबन, दान कक्ष की चाबियां अनधिकृत लोगों के पास रहने और वित्तीय प्रक्रियाओं में लापरवाही जैसे आरोप लगाए गए हैं। विश्व सिंधी सेवा संगम ने भी वर्ष 2021 में मंदिर को दान की गई लगभग दो सौ किलोग्राम चांदी की ईंटों का विधिवत रसीद नहीं मिलने और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। दूसरी ओर ट्रस्ट ने भी कुछ कर्मचारियों से जुड़ी पहचान निरस्त करने और दर्शन व्यवस्था में बदलाव जैसे कदम उठाए हैं। इन



सबके बीच एसआईटी की जांच और न्यायालय की प्रक्रिया ही अंतिम सत्य का आधार बनेगी।

यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आरोप हैं, फैसला नहीं। न्यायालय ने केवल जवाब मांगा है, किसी को दोषी घोषित नहीं किया है। इसलिए मीडिया, राजनीति और समाज—तीनों की जिम्मेदारी है कि वे न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें। किसी को पहले से दोषी ठहराना भी अनुचित है और बिना जांच के हर आरोप को साजिश बताकर खारिज कर देना भी उतना ही गलत है।

लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक बड़ा सवाल अवश्य खड़ा किया है। क्या भारत की बड़ी धार्मिक संस्थाओं में वित्तीय पारदर्शिता की व्यवस्था पर्याप्त है? मंदिरों, गुरुद्वारों, मठों, दरगाहों और अन्य धार्मिक संस्थानों में हर वर्ष हजारों करोड़ रुपये का दान आता है। यह धन किसी कर के रूप में नहीं आता, बल्कि लोगों की आस्था का प्रतीक होता है। इसलिए उसका प्रबंधन भी उसी स्तर की पवित्रता और पारदर्शिता से होना चाहिए।

देश के कुछ प्रमुख धार्मिक संस्थानों ने आधुनिक वित्तीय प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डिजिटल लेखा प्रणाली, ऑनलाइन दान, सीसीटीवी निगरानी, नियमित ऑडिट और सार्वजनिक आय-व्यय विवरण जैसी व्यवस्थाएं धीरे-धीरे बढ़ रही हैं। लेकिन अनेक स्थानों पर अब भी पारंपरिक व्यवस्था, सीमित निगरानी और अपर्याप्त जवाबदेही बनी हुई है। जब संस्थाओं का आकार और दान की मात्रा बढ़ जाती है, तब केवल परंपरा के भरोसे व्यवस्था नहीं चल सकती। आधुनिक प्रबंधन और पारदर्शिता को स्वीकार करना समय की आवश्यकता है।

दुर्भाग्य यह है कि भारत में धार्मिक संस्थाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठते ही बहस का स्वरूप बदल जाता है। लोग तुरंत इसे धर्म बनाम अधर्म या आस्था बनाम षड्यंत्र की बहस बना देते हैं। जबकि वास्तविक प्रश्न केवल इतना है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया धन सुरक्षित है या नहीं और उसका उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुसार हो रहा है या नहीं। यह प्रश्न किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि धर्म की गरिमा के पक्ष में है।

आस्था कभी भी पारदर्शिता से कमजोर नहीं होती। बल्कि पारदर्शिता आस्था को और मजबूत करती है। यदि किसी संस्था का लेखा-जोखा साफ है, उसकी प्रक्रियाएं स्पष्ट हैं और उसकी कार्यप्रणाली सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरी उतरती है, तो उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ती है। जो संस्था स्वयं को जनता के प्रति जवाबदेह मानती है, उसके प्रति विश्वास भी अधिक गहरा होता है।

राम का पूरा जीवन सत्य, मर्यादा और उत्तरदायित्व का संदेश देता है। राम ने सत्ता को अधिकार नहीं, दायित्व माना। उन्होंने राजा होकर भी स्वयं को लोकमत और नैतिकता से ऊपर नहीं रखा। रामराज्य की अवधारणा केवल समृद्धि की नहीं, बल्कि न्याय, समानता और पारदर्शी शासन की अवधारणा है। यदि राम के नाम पर बने सबसे बड़े मंदिर में भी पारदर्शिता की मांग उठती है, तो उसे राम के आदर्शों के विरुद्ध नहीं, बल्कि उन्हीं के अनुरूप समझा जाना चाहिए।

यह विवाद एक अवसर भी हो सकता है। यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है और उसके आधार पर देश के सभी बड़े धार्मिक ट्रस्टों के लिए आधुनिक वित्तीय मानक तय किए जाते हैं, तो इससे धार्मिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और मजबूत होगी। हर बड़े धार्मिक ट्रस्ट के लिए स्वतंत्र वार्षिक ऑडिट, ऑनलाइन आय-व्यय विवरण, डिजिटल इन्वेंट्री, सीसीटीवी आधारित निगरानी, दान की वस्तुओं का वैज्ञानिक अभिलेखीकरण और समय-समय पर सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करना अनिवार्य बनाया जा सकता है। इससे न केवल विवाद कम होंगे, बल्कि श्रद्धालुओं का विश्वास भी बढ़ेगा।

अपने विसर्जन पर क्यों उतारू है पाकिस्तान

राजेश बादल

दुनिया के नक्शे में उभरने के बाद क्या कोई मुल्क इतना मासूम और अपरिपक्व हो सकता है कि वह अपनी हरकतों से अपने विसर्जन की पटकथा लगातार लिखता रहे? शायद नहीं। लेकिन, पाकिस्तान के मामले में यह बात दावे से कही जा सकती है। गुजिश्ता 79 बरस में इस देश ने मुसलसल हिंदुस्तान से नफरत के बीज बोये हैं। अब यह बीज कांटे बनकर उसकी देह को लहूलुहान कर रहे हैं और मुल्क समझने को तैयार नहीं है। संसार में बीती शताब्दी में जो देश अस्तित्व में आए, वे आज अपने ढंग से मानव समुदाय को कुछ न कुछ दे ही रहे हैं। पाकिस्तान इसका अपवाद है।

छल, कपट, फरेब और खून-खराबे का सहारा लेकर यह तथाकथित राष्ट्र सबसे लेता ही रहा है। यहां तक कि अपनी अवाम को भी यह कुछ न दे सका। भ्रष्टाचार, कट्टरता, महंगाई, तानाशाही, उन्माद, विकृत इतिहास और धोखे के अलावा पाकिस्तान के नियंताओं ने अपने देश के लोगों को दिया ही क्या है?

जिसने वह मुल्क अंग्रेजों से भीख मांगकर लिया और जिसे पाकिस्तानी कायदे-आजम कहते थे, अपने जीवनकाल में ही वह काफिर-ए-आजम कहा जाने लगा। जो बलूचिस्तान बंटवारे के वक्त आजाद राष्ट्र था, उसे धोखे से कब्जाया, कश्मीर पर कबायलियों के वेश में फौज भेजकर एक हिस्सा अपने देश में मिलाया, अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हड़पा, बांग्लादेश के लोगों को उनके जायज हक नहीं दिए, अपने घर में निर्वाचित प्रधानमंत्री को सूली पर लटकाया, गोरों की तरह फौज ने जमकर शोषण किया और संविधान को बार-बार बदलकर उसका मजाक बना दिया।

बांग्लादेश खोने के बाद अब वहां की सेना बलूचिस्तान और अपने कब्जे वाले कश्मीर को खोने पर उतारू है। इसके बाद जो पाकिस्तान बचेगा, वह जुगनू की मानिंद दुनिया के नक्शे में टिमटिमाता रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर इन दिनों जल रहा है। बुधवार को इस इलाके में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ।

इसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा अहमद आसिफ पर आंदोलनकारियों ने काली स्याही फेंकी। उन्हें उल्टे पैरों भागना पड़ा। वे



चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। पर सुरक्षाबलों ने करीब दो दर्जन निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस बार वहां आग की लपटें इतनी तेज हैं कि वे देश के बाकी हिस्सों को भी झुलसाने लगी हैं।

इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है कि किसी देश की फौज ही अपने नागरिकों को गोली चलाकर भून डाले। नागरिकों का अपराध यह है कि वे अपने अधिकार चाहते हैं। हुकूमत ने उनकी राशन की आपूर्ति रोक दी है। उनके घरों में अब बिजली के लट्टू नहीं चमकते। आजादी के समय जो लैंप जलते थे, वही अब रौशनी दे रहे हैं।

डीजल और पेट्रोल पंप बंद हैं क्योंकि सरकार की तरफ से सप्लाई बंद है। लोगों को कालाबाजारी करने वाले फौजी दलालों से ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। गेहूं, आटा, मसाले और सब्जियां लाने वाले ट्रक सत्ताधीशों ने रोक दिए हैं। भूखी अवाम हिंसा पर उतारू नहीं होगी तो क्या करेगी? यह तो तब है जब उस क्षेत्र में असेंबली के चुनाव सिर पर हैं।

होता तो यह है कि जब चुनाव आते हैं तो सरकार जरूरी चीजों के दाम गिरा देती है, बहुत सी वस्तुएं उन्हें मुफ्त मुहैया कराती है और मतदाताओं को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। जब यह मुश्किल हुई तो आम जनता के नुमाइंदों ने संयुक्त जन कार्रवाई समिति (जेएएसी) बनाई और आंदोलन शुरू कर दिया। सरकार इस आंदोलन को कुचलना चाहती है।

असेंबली के चुनाव इस महीने की 27 तारीख को होंगे। हुकूमत ने इस बार कुल 45 में से 12 स्थान मुहाजिरों यानी शरणार्थियों के लिए सुरक्षित कर दिए हैं। संयुक्त जन कार्रवाई समिति चाहती है कि इन 12 सीटों पर आरक्षण समाप्त किया जाए। उनके दो तर्क हैं। एक तो यह कि इन सीटों पर पाकिस्तान के अन्य प्रदेशों से आकर लोग चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में उनकी नुमाइंदगी के सच्चे प्रतिनिधि वे नहीं हो सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात वे कह रहे हैं कि अविभाजित हिंदुस्तान से अलग होकर बना पाकिस्तान पूरी तरह मजहब की बुनियाद पर टिका है। अर्थात जितने भी मुसलमान यहां हैं, वे अधिकतर भारत से ही आए हैं। जब किसी देश का आधार मजहब है तो उनमें भेद कैसा? इस तरह तो लगभग समूचा पाकिस्तान ही शरणार्थी है।

हुक्मरानों ने उन्हें सुन्नी, शिया, पठान, मुहाजिर, बलूची, बोहरा और अहमदिया मुसलमानों में बांट दिया। सुन्नियों की आबादी सबसे ज्यादा है। इसलिए वे ही अपने को असली मुसलमान मानते हैं। बाकी सबके साथ दोयम दर्जे का बरताव होता है। सबूत के तौर पर वे कहते हैं कि बांग्लादेश तो इसीलिए बना था कि वे बांग्ला भाषा बोलते थे, उर्दू नहीं।

इसलिए पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया और उर्दू तो अभी भी सत्तर फीसदी मुसलमानों को नहीं आती। वे पंजाबी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, डोगरी मिश्रित कश्मीरी, गुजरी और उर्दू हिंदी बोलते हैं। सरकार का तर्क है कि जो लोग विभाजन के समय जम्मू और पाकिस्तान से आए थे, वे राष्ट्र के अनेक प्रांतों में बसे हैं। वे भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं।

आंदोलनकारियों ने इस बेतुकी बात को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि फिर तो पूरे पाकिस्तान को ही आरक्षण देना पड़ेगा क्योंकि मुसलमान तो बिहार, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश से भी गए थे। उनके बारे में हुकूमत क्या कहेगी? कमोबेश यही स्थिति बलूचिस्तान की है। वहां बलूची लड़ाकों ने सरकार की नाक में दम कर रखा है।

उधर अफगानिस्तान सीमा पर पठानी तालिबान से लड़ना पाकिस्तानी सेना के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। वहां तो बलूचिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया है। लब्बोलुआब यह कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर इस बार निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। वहां की अवाम बांग्लादेश के रास्ते पर चल पड़ी है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से इस मामले में पहल करने का आह्वान किया है। चिंता यह है कि यदि पाक कब्जे में रह रहे लोग जबरन भारत की सीमा में दाखिल होंगे तो उनके लिए दरवाजे खोलने के अलावा क्या रास्ता रह जाएगा?

भाजपा सरकार हृदयहीन, विपक्ष असंवेदनशील, मौका परस्त?

सनत जैन

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ अनशन में भूखहड़ताल कर रहे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की है। 19 दिन अनशन के पूरे हो चुके हैं और उनका वजन 8 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। जो डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं उन्होंने उनकी जिंदगी को लेकर चिंता जताई है। इस चिंता को देखते हुए विपक्ष ने भी बयान-बाजी करना शुरू कर दी है। सपा नेता अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से अपील करते हुए कहा, भाजपा सरकार के लिए किसी के जीवन का कोई महत्व नहीं है। हम उनसे विनम्र आग्रह करते हैं कि वह अनशन तोड़ दें। उनका जीवन मानवता और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। लोकतंत्र के लिए जिस भाजपा नेतृत्व वाली सरकार को जगाने के लिए वह अनशन पर हैं वह एक सिद्धांतहीन, भ्रष्ट तंत्र, असंवेदनशीलता और हृदयहीनता वाली सरकार है। उसके लिए किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है। पिछले एक सप्ताह से विपक्ष के नेता सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस लड़ाई में साथ देने के लिए विपक्ष और आम जनता जिनकी वह लड़ाई लड़ रहे हैं वह सब शांति के साथ तमाशा देख रहे हैं। यदि आम जनता और विपक्ष जिम्मेदार और संवेदनशील होता तो वह उनके समर्थन में आंदोलन और इस लड़ाई को लड़ने के लिए उनके साथ खड़ा होता। यह तो हुआ नहीं, सारा विपक्ष सरकार को कोस रहा है, लेकिन सरकार से लड़ने के लिए ना तो विपक्ष एकजुट हो रहा है नाही आम जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ने आ रही है। भाजपा सरकार की स्पष्ट धारणा है, जनता को यदि तकलीफ होगी तो वह स्वंय सड़कों पर उतर आएगी, लेकिन यदि जनता सड़कों पर नहीं है तो इसका मतलब उसे कोई तकलीफ नहीं है। विपक्ष यदि एकजुट नहीं है ऐसी स्थिति में सरकार यह मानकर चलती है कि उसे और उसकी सरकार की नीतियों पर जनता का समर्थन प्राप्त है। जो सरकार में बैठे हैं वह सत्ता के सुख भोग रहे हैं। विपक्ष में बैठे नेता सत्ता तक पहुंचने के लिए अलग-अलग राजनीति कर रहे हैं। जनता के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। देश की समस्याओं के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं वह अपने राजनीतिक हितों और पारिवारिक हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के संविधान और लोकतंत्र तथा गरीबों की यदि उन्हें चिंता होती तो सारा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता। वांगचुक जैसे पर्यावरण विद् जब पर्यावरण और स्वतंत्रता के साथ विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ने के लिए अनशन जैसे कठोर कदम उठाते हैं, ऐसे समय पर भी यदि विपक्ष एकजुट नहीं होता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। इसके पहले भी पर्यावरणविद् प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की मौत अनशन के दौरान हो चुकी है। 111 दिन वे आमरण अनशन पर बैठे रहे। सारा विपक्ष अलग-थलग रहा। सरकार के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा माकूल है। सरकार सोचती है, जब जनता और विपक्ष उनकी नीतियों और सत्ता से सहमत है, तभी तो कोई विरोध दर्ज नहीं करा रहा है। जब तक संपूर्ण विपक्ष ईमानदारी के साथ संविधान, लोकतंत्र तथा आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट नहीं होगा, जनता को जब तक वह यह विश्वास नहीं दिलाएगा कि विपक्ष जनता की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसी स्थिति में जनता उनके साथ कैसे खड़ी होगी? इसे आसानी से समझा जा सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसा मंच है जिसने मुख्य न्यायाधीश द्वारा युवाओं को कॉकरोच कहने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर बनी थी। इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन इसी के मंच पर जाकर सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू कर दिया, जिसके कारण इतने बड़े पर्यावरण और शिक्षा के मुद्दे में वह एक तरह से अलग-थलग पड़ गए हैं। सरकार भी इसी का फायदा उठा रही है। विपक्ष भी कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर जाने से बच रहा है। लेकिन यह एक ऐसा मामला है जब सारे लोगों को मिलकर पर्यावरण और छात्रों की मांग उठानी चाहिए। राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम जनता को भी इस लड़ाई में साथ आना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जिस तरह से पहले भी अनशन और आंदोलन के दौरान कई लोगों की जान भेंट चढ़ चुकी है, आशंका है ऐसी ही एक भेंट सोनम वांगचुक की चढ़ सकती है। सरकार और विपक्ष की सोच में कोई अंतर नजर नहीं आता है यही कहा जा सकता है।

महादेव के कई चमत्कारी रूप हैं भगवान शिव सौम्य प्रकृति एवं रौद्ररूप दोनों के लिए विख्यात हैं। अन्य देवों से शिव को भिन्न माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं।

सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले महादेव भोलेबाबा के नाम से अपने भक्तो में प्रसिद है



भोले-भंडारी शिव-शंकर अपने भक्तों को हर संकट से उबारते हैं, मुश्किल घडी में उन्हें राह दिखाते हैं। तभी तो देवता भी अपने कष्टों के निवारण के लिए भोले-भंडारी की ही शरण में जाते हैं।

भोले-भंडारी शिव-शंकर अपने भक्तों को हर संकट से उबारते हैं, मुश्किल घडी में उन्हें राह दिखाते हैं। तभी तो देवता भी अपने कष्टों के निवारण के लिए भोले-भंडारी की ही शरण में जाते हैं। महादेव के कई चमत्कारी रूप हैं भगवान शिव सौम्य प्रकृति एवं रौद्ररूप दोनों के लिए विख्यात हैं। अन्य देवों से शिव को भिन्न माना गया है।

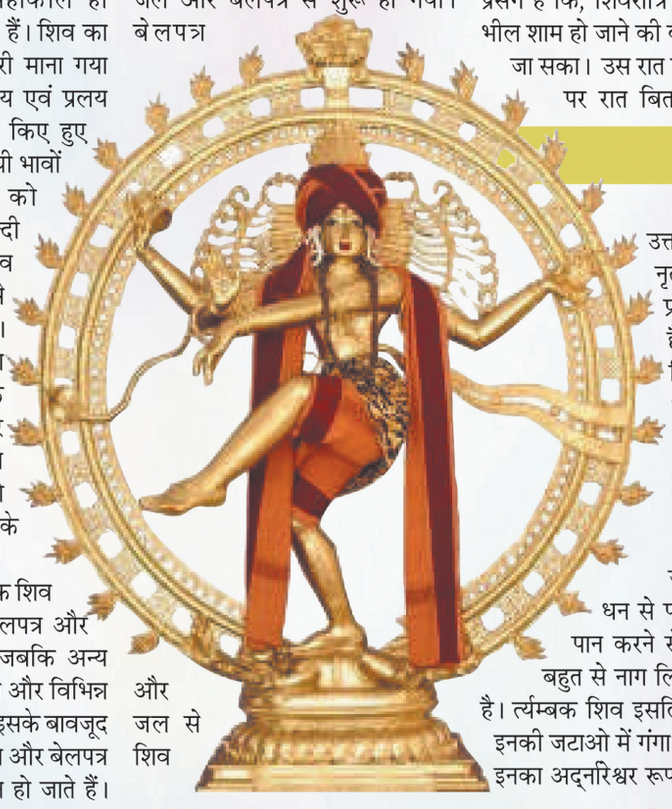
सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदिस्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिषशास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले यह महादेव भोलेबाबा के नाम से अपने भक्तो में प्रसिद है। यह महातपस्वी महा अघोरी और तंत्र मंत्र के रचियता है। तांत्रिको और अघोरियो के यह परम आराध्य है इन्होने अनेको अवतार जनकल्याण के लिए लिया है।

आपने देखा होगा कि शिव भक्त भोले बाबा को बेलपत्र और भांग धतूरा चढाते हैं। जबकि अन्य देवी देवताओं को मिष्ठान और विभिन्न प्रकार के भोग चढाते हैं। इसके बावजूद भी भोले बाबा भांग धतूरा और बेलपत्र चढाने वाले पर मेहरबान हो जाते हैं।

भगवान भोलेनाथ को यह सभी चीजें पसंद क्यों है इसका उत्तर पुराणों में मिलता है। पुराणों के अनुसार सागर मंथन के समय जब हालाहल नाम का विष निकलने लग तब विष के प्रभाव से सभी देवता एवं जीव-जंतु व्याकुल होने लगे। ऐसे समय में भगवान शिव ने विष को अपनी अंजुली में लेकर पी लिया। विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए शिव जी ने इसे अपनी कंठ में रख लिया इससे शिव जी का कंठ नीला पड गया और शिव जी नीलकंठ कहलाने लगे।

लेकिन विष के प्रभाव से शिव जी का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क पर जल उडलेना शुरू किया जिससे मस्तिष्क की गर्मी कम हुई। बेल के पत्तों की तासीर भी ठंढी होती है इसलिए शिव जी को बेलपत्र भी चढाया गया।

इसी समय से शिव जी की पूजा जल और बेलपत्र से शुरू हो गयी। बेलपत्र और जल से शिव जी का मस्तिष्क शीतल रहता और उन्हें शांति मिलती है। इसलिए बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि की कथा में प्रसंग है कि, शिवरात्रि की रात में एक भील शाम हो जाने की वजह से घर नहीं जा सका। उस रात उसे बेल के वृक्ष पर रात बितानी पडी। नींद आने से वृक्ष से गिर न जाए इसलिए रात भर बेल के पत्तों को तोडकर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से शिव जी प्रसन्न हो गये। शिव जी भील के सामने प्रकट हुए और परिवार सहित भील को मुक्ति का वरदान प्राप्त हुआ।



नटराज रूप :

इस रूप में शिवजी नृत्य करते नजर आते है। यह सबसे उत्तम नर्तक और नृत्य के जनक कहलाते है। इनका तांडव नृत्य सबसे प्रमुख है। यह तांडव दोनों रूपों में है एक प्रलयकारी तांडव जो शिव के क्रोधित होने पर किया जाता है। और अन्य सौम्य तांडव जो शिव के प्रसन्न होने पर किया जाता है। रौद्र तांडव शिवजी करने से वो रूद्र कहलाते थे जिससे सृष्टी में महाविनाश आ जाता है।

कैसे दिखाई देते है भोलेनाथ :

जटाधारी शिव एक तपस्वी की तरह दिखते है जो माया धन से परे है। भस्म से अपना श्रृंगार करते है। हलाहल विष का पान करने से यह नीलकंठ वाले है। इनकी जटाओ और शरीर पर बहुत से नाग लिपटे हुए है। रुद्राक्ष की माला जटा पर हाथो पर बंधी हई है। त्र्यम्बक शिव इसलिए कहलाते है क्योकि इनके एक तीसरी आँख भी है। इनकी जटाओ में गंगा और शीश पर अर्धचन्द्रमा सुशोभित है। माँ शक्ति के साथ इनका अद्नरिश्वर रूप जगत रचियता है।

ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होकर सारे विघ्नों को दूर करते हैं

जिसके कारण भगवान गणेश की पूजा करने का सबसे शुभ दिन है। शिव-पार्वती के पुत्र गणेश जी को हम कई नामों से जानते है जैसे कि सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशन, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। जिन्हे हम कष्टो को हरने वाला मानते है।

सर्वप्रथम गणेशजी की पूजा हर दिन हर घर में की जाती है। सच्चे मन से गणेश की पूजा की जाए तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बुधवार के दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व है।

''वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ।।''

हे भव्य शरीर, वक्र सूंड, दश लक्ष सूर्यों की चमक वाले गणेशजी, मेरे सारे कर्मों को विघ्नों से हमेशा मुक्त करते रहना। सर्वप्रथम पूज्य गणेशजी की पूजा तो हर दिन हर घर में की जाती है। सच्चे मन से गणेश की पूजा की जाए तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बुधवार के दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व है। जिसके कारण भगवान गणेश की पूजा करने का सबसे शुभ दिन है। शिव-पार्वती के पुत्र गणेश जी को हम कई नामों से जानते है जैसे कि सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशन, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। जिन्हे हम कष्टो को हरने वाला मानते है।

ऐसे करें पूजा

बुधवार या विनायक चतुर्थी के दिन ब्रहम मूहुर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। और भगवान की पूजा करें। इसके बाद दोपहर के समय अपनी इच्छा अनुसार सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी भगवान श्रीगणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद संकल्प मंत्र पढे और फिर श्री श्रीगणेश की षोडशोपचार (सोलह सामग्रियों से) पूजन-आरती करें। भगवान गणेशजी की मूर्ति पर सिंदूर चढाएं। इसके बाद ऊं गं गणपतयै नम: मंत्र का उच्चारण करते हुए 21 दूर्वा दल चढाएं। और बोग में गुड या बूंदी के 21 लड्डुओं खिलाएं।

इनमें से 5 लड्डु मूर्ति के पास रख दें तथा 5 ब्राहमण को दान कर दें। शेष लड्डु प्रसाद के रूप में बांट दें। इसके बाद पूजा में भगवान श्रीगणेश स्त्रोत, अथर्वशीर्ष, संकटनाशक स्त्रोत आदि का पाठ करें। ब्राहमणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा प्रदान करने के बाद शाम के समय स्वयं भोजन ग्रहण करें। संभव हो तो उपवास करें। इस व्रत का आस्था और श्रद्धा से पालन करने पर भगवान श्रीगणेश की कृपा आप पर बनी रहेगी।

आप जिस काम में हाथ डालोंगे उसमें आपको सफलता जरुर मिलेगी। गणेशजी सभी विघ्नों को हरने वाले और रिद्धि-सिद्धि के दाता माने जाते हैं। इसलिए संबंधित बाधाएँ और विघ्नों को रोकने के लिए गणेशजी की उपासना की जाती है, ताकि मन संयमित रहे और किसी अनिष्ट कार्य का आचरण न हो। संकट चतुर्थी व्रत करने से आप के जीवन में आए हुए हरेक प्रकार के संकट दूर होते हैं और यदि किसी भी प्रकार का दोषारोपण लगा हो तो दूर होता है। समाज में मान-प्रतिष्ठा मिलती है। आयुष्य और बल में वृद्धि होती है और सर्वत्र आप की कीर्ति फैलती है। जलस्नान कराने से जीवन से दु:ख का नाश होता है और सुख का आगमन होता है। जीवन में विद्या, धन संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफेद पुष्प अथवा जासुद अर्पण करने से कीर्ति मिलती है। दुर्वा अर्पण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आर्थिक उन्नति होती है और संतान का सुख मिलता है। सिंदूर अर्पण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धूप अर्पण करने से कीर्ति मिलती है। लड्डु अर्पण करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।



यह व्रत सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम कर सौभाग्य में वृद्धि व चर्म, नैत्र विकार नाशक भी है

सूर्य की उपासना अति फलदायक होती है। सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और सूर्य को प्रबल बनाने के लिए रविवार का व्रत करना बहुत ही फलदायक है। इस व्रत को करने से आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है।

सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष दिखतें हैं। सूर्य की उपासना अति फलदायक होती है। सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और सूर्य को प्रबल बनाने के लिए रविवार का व्रत करना बह सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष दिखतें हैं। सूर्य की उपासना अति फलदायक होती है। सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और सूर्य को प्रबल बनाने के लिए रविवार का व्रत करना बहुत ही फलदायक है। इस व्रत को करने से आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। एवं सर्व कामना सिद्धि भी प्राप्त होती है। यह व्रत चर्म और नैत्र आदि विकार नाशक भी है। इस व्रत को निम्न तरीके से पूर्ण श्रद्धा के साथ करे। दिनभर व्रत रखकर सायंकाल अग्निहोत्र आदि कर बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार महीने में प्रत्येक रविवार को सूर्य की उपासना करने से दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। रविवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से प्रारंभ करे और एक वर्ष अथवा 12 या 30 रविवार तक करे। रविवार के दिन प्रात: स्नान आदि करके लाल वस्त्र धारण करे एवं मस्तक पर लाल चन्दन का तिलक करे तथा ताम्बे के कलश में जल लेकर उसमे रोली, अक्षत, लाल पुष्प डालकर श्रद्धापूर्वक सूर्यनारायण को अर्ध्य प्रदान करे।

एवं ''ऊँ हा हीं हौं स: सूर्याय नम:'' इस बिज मंत्र का यथाशक्ति जाप करे। इस दिन भोजन सूर्यास्त से पहले करे। भोजन में गेहू की रोटी अथवा गेहू का दलिया या इस का हलवा बनाये।भोजन से पूर्व इस हलवा का कुछ भाग देवस्थान या बालक-बालिका को देकर भोजन करे। भोजन में प्रथम हलवा ग्रहण करे फिर अन्य पदार्थ ग्रहण करे। भोजन में नमक का प्रयोग ना करे। अंतिम रविवार को हवन क्रिया के पश्चात योग्य दम्पति को भोजन कराकर लाल वस्त्र एवं यथेच्छा दक्षिणा प्रदान करे।



इसलिए सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है

मन अशांत रहे, उसमें उथल-पुथल मची रहे, तो तन शांत व स्वस्थ कभी भी नहीं रह सकता। महर्षि अरविंद कहते हैं, मन अशांत रहे, उसमें उथल-पुथल मची रहे, तो तन शांत व स्वस्थ कभी भी नहीं रह सकता। इससे शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी जन्म ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है। किसी बात पर यदि क्रोध आता है, तो हम अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इससे बात बिगड जाने की आशंका बनी रहती है। इसलिए मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है।

सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार, जीवन में एक बार किसी कर्म को करने का फैसला ले लिया, तो फिर पीछे मुड कर न देखें। बार-बार पीछे मुडकर देखने वाले इतिहास नहीं बना पाते हैं।

धृष्टकेतुश्चेकितान: काशिराजश्च वीर्यवान
पुरुजित्कुंतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव:।।
धृष्टकेतु- दृढकर्तव्य, चेकितान:
- जहां भी जाए , वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना,काशिराज: - कायारूपी काशी में ही वह साम्राज्य है, पुरुजित - स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित, कुंतिभोज: - कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ, शैब्य अर्थात सत्य व्यवहार - युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान
सौभद्रो दौपदेयाश्च सर्व एव महारथा:।।
और पराक्रमी युधामन्यु: - युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमौजा: - शुभ की मस्ती, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु
- जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है - ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन, ध्यानरूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र - वात्सल्य, लावण्य, सहदयता, सौम्यता, स्थिरता सब के सब महारथी हैं। साधन-पथ पर संपूर्णयोग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं।



हनुमानजी ऐसे पूज्य देव हैं, जो कलियुग में भी साक्षात् रहते हैं। वह ब्रहमचारी और प्रभु श्रीराम के अमिट भक्त हैं। लेकिन पवनपुत्र के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो वर्तमान में किसी रहस्य से कम नहीं। इन बातों की उल्लेख हिदू धार्मिक ग्रंथो और रामायण के तमाम संस्करणों में उल्लेख मिलता है। जैसे कि...



हनुमानजी ऐसे पूज्य देव हैं, जो कलियुग में भी साक्षात् रहते हैं

हनुमानजी भगवान शिव के अवतार हैं। वह शक्ति, भक्ति, और दृढता का प्रतीक हैं।

१.हनुमानजी भगवान शिव के अवतार हैं। वह शक्ति, भक्ति, और दृढता का प्रतीक हैं।

२.हनुमानजी की मां पूर्वजन्म में अप्सरा थीं। जो एक शाप के कारण पृथ्वी पर जन्मीं और भगवान शिव के अवतार हनुमानजी की मां बनने का सौभाग्य मिला।

३.हनुमानजी बचपन से ही भगवान श्रीराम को अपना आराध्य देव मानते थे। और जब वह श्रीराम से वह मिले तो प्रसन्नता के आंसुओं को रोक नहीं पाए।

४.जब श्रीराम के अनुज लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब हनुमानजी अपने एक हाथ पर ही पूरा एक पर्वत ले आए थे। वह इसीलिए क्योंकि उस पर्वत पर संजीवनी बूटी थी। जिससे से लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था से दूर किया जा सके।

५.गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित हनुमान चालीसा का पाठ यदि मंगलवार और शनिवार को किया जाए तो बजरंगबली की कृपा उस भक्त पर हमेशा बनी रहती है। जब श्रीराम की मृत्यु हुई तब हनुमानजी ने यम (मृत्यु के देवता) पर जाने से रोका था। लेकिन बाद में स्थितियां बदलीं और श्रीराम विष्णुलोक गए।

६.हनुमानजी ने श्रीराम को अंतिम समय में यह वचन दिया था। कि वह पृथ्वी पर अदृश्य रूप में रहकर राम नाम का स्मरण करते हुए उन्हें महाप्रलय तक पूजते रहेंगे। इसीलिए माना जाता है हनुमानजी

७.आज भी हमारे बीच में हैं। और उन्हें सच्चे मन से याद किया जाए तो वह भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सेक्युलर हो तो मस्जिद में भी हनुमान चालीसा कराओ: योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में आयोजित पंचायत आजतक उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों और पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला बोला. साथ ही कानून-व्यवस्था, धार्मिक सौहार्द और प्रदेश की बदलती तस्वीर को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. सीएम योगी ने विपक्ष की सेक्युलर राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि अयोध्या के हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का काम किया गया था, तो फिर किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया जाना चाहिए था. उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों के दौरान अक्सर तनाव की स्थिति पैदा हो जाती थी. कई स्थानों पर पथराव-हिंसा की घटनाएं होती थीं और कर्फ्यू तक लगाना पड़ता था. लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।



उद्धव सेना ने बागी सांसदों को भेजा नोटिस

मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने पार्टी छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए अपने छह लोकसभा सांसदों को कानूनी नोटिस भेजा है. पार्टी का कहना है कि मूल राजनीतिक दल के विलय के बिना संसदीय दल का विलय कानूनन संभव नहीं है. वहीं, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस नोटिस को बेअसर बताते हुए कहा कि उनके सांसदों ने इस पत्र को कूड़ेदान में फेंक दिया और इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है.शिवसेना के संसदीय दल के नेता अरविंद सावंत ने 13 जुलाई को भेजे गए नोटिस में बगावत करने वाले 6 सांसदों से कहा कि उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में और शिवसेना के चुनाव चिह्न पर लड़कर जीता था. उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव में इन सांसदों ने शिंदे गुट के उम्मीदवारों के खिलाफ जीत हासिल की थी।



दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तारीख बढ़ी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने दिल्ली में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया की टाइमलाइन में बदलाव कर दिया है. अब दिल्ली की फ़ाइनल इलेक्टोरल रोल 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी. पहले इसे 7 अक्टूबर को प्रकाशित किया जाना था. इस बदलाव के साथ स्क्रुक्र प्रक्रिया के बाकी सभी चरण भी आगे खिसक गए हैं. यह फैसला दिल्ली के चीफ़ इलेक्टोरल ऑफ़िसर की ओर से 14 जुलाई को अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद लिया गया. चुनाव आयोग ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है. अब बूथ लेवल ऑफिसर्स की घर-घर जाकर वेरिफ़िकेशन करने की अवधि 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. पहले यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक पूरी होनी थी. यानी फील्ड वेरिफिकेशन के लिए करीब 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है. चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करने की तारीख भी बदल दी है. अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 17 अगस्त को प्रकाशित होगी।



बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ी खबर सामने आई है. तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मदन मित्रा पार्टी के बागी खेमे में शामिल हो गए हैं. यह बागी खेमा विपक्ष के नेता ऋ्रब्रत बनर्जी के नेतृत्व में चल रहा है. ये पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है. मदन मित्रा पार्टी के पुराने और अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं. वह पहले भी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. ऐसे में बागी खेमे में शामिल होने का सीधा असर टीएमसी की अंदरूनी राजनीति पर पड़ेगा. पार्टी के भीतर पहले से ही असंतोष की खबरें आती रही हैं और अब इस नए घटनाक्रम ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है. मंगलवार रात मदन मित्रा अचानक एंटाली के पूर्व विधायक स्वर्णकमल साहा के घर पहुंचे थे. यहीं से उनके पाला बदलने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं. स्वर्णकमल साहा के बेटे संदीपन साहा खुद एंटाली से विधायक हैं।



भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट का डेटा लीक

नई दिल्ली। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़े हजारों संवेदनशील दस्तावेज डार्क वेब पर लीक होने का मामला सामने आया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रैनसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने प्लांट की ब्लूप्रिंट, सप्लायर विवरण, निरीक्षण रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी दस्तावेज जारी किए हैं. ये डेटा कथित तौर पर प्लांट के ठेकेदार रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर से चोरी हुआ. कंपनी ने आंशिक डेटा उल्लंघन की पुष्टि की है. मामले की जांच CERT-In और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं. वर्ल्ड लीक्स का दावा है कि ये डेटा अनिल अंबानी के रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर का है. हालांकि, इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है. रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस ग्रुप ने स्वीकार किया कि तीसरे पक्ष के डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर Yotta के सर्वर पर उसके डेटा में आंशिक सेंध की गई थी. कंपनी ने कहा कि इस घटना की जानकारी सरकार को दे दी गई है, लेकिन यह नहीं बताया कि कौन सा डेटा प्रभावित हुआ।



सैफुद्दीन सोज ने जम्मू-कश्मीर को लेकर कह दी खतरनाक बात

भाजपा ने कांग्रेस की खामोशी पर उठाये तीखे सवाल

नईदिल्ली। जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफ़ुद्दीन सोज ने जिस तरह बहस का रुख अनुच्छेद 370 की बहाली और तथाकथित अंदरुनी स्वायत्तता की ओर मोड़ने की कोशिश की है, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोज ने साफ कहा कि नेशनल कांफ्रेंस को जंतर मंतर पर केवल राज्य का दर्जा मांगने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए भी संघर्ष करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का असली मुद्दा अंदरुनी स्वायत्तता है और यह उनकी अपनी शर्तों पर बहाल होनी चाहिए।

सोज का बयान केवल राजनीतिक मांग भर नहीं है। उन्होंने इसे धार्मिक बहुलता के संदर्भ से भी जोड़ा। उनका कहना था कि मुस्लिम बहुल जम्मू-कश्मीर ने हिंदू बहुल भारत के साथ विलय का फैसला किया था और वह फैसला सही था, लेकिन अब अंदरुनी स्वायत्तता उनकी अपनी शर्तों पर बहाल होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या किसी राज्य और राष्ट्र के संबंधों की बुनियाद धर्म और अलग शर्तों पर टिक सकती है? क्या भारत का संविधान किसी राज्य को अपनी शर्तों पर राष्ट्रीय ढांचे के भीतर रहने की अवधारणा स्वीकार करता है? सोज की यह सोच केवल विवादास्पद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श को उलझाने वाली भी दिखाई देती है।

दिलचस्प यह भी है कि सोज ने राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे को लगभग गौण बताते हुए कहा कि उसे कोई हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रख सकता, इसलिए असली लड़ाई अनुच्छेद 370 और अंदरुनी स्वायत्तता की है। इससे यह संदेश जाता है कि राज्य का दर्जा उनके लिए प्राथमिक विषय नहीं, बल्कि विशेष संवैधानिक व्यवस्था की वापसी ही मुख्य लक्ष्य है।

उधर, सोज के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने



इसे राष्ट्रविरोधी बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से स्पष्ट जवाब मांगा कि क्या यह कांग्रेस का आधिकारिक रुख है। उनका कहना था कि यदि कांग्रेस सोज के बयान से सार्वजनिक रूप से दूरी नहीं बनाती और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, तो इसे पार्टी की आधिकारिक सोच माना जाएगा। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि अंदरुनी स्वायत्तता की मांग भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक संदेश देती है।

देखा जाये तो अब सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने है। क्या सैफुद्दीन सोज का बयान उनकी व्यक्तिगत राय है या पार्टी की राजनीतिक सोच? यदि यह निजी विचार हैं तो कांग्रेस अब तक स्पष्ट खंडन क्यों नहीं कर रही? और यदि पार्टी इस सोच से सहमत है तो क्या वह देश को यह बताने का साहस करेगी कि जम्मू-कश्मीर पर उसका वास्तविक रुख क्या है? इस पूरे विवाद ने केवल सोज की सोच को ही कठघरे में नहीं खड़ा किया है, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व की चुप्पी को भी कटघरे में ला खड़ा किया है। देश अब बयान नहीं, बल्कि स्पष्ट और दो टूक जवाब चाहता है।

ममता बनर्जी को बड़ा झटका

टीएमसी सांसद कोएल मलिक ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा

नईदिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमस) प्रमुख ममता बनर्जी को गुरुवार को एक और राजनीतिक झटका लगा, जब अभिनेत्री से नेता बनीं और राज्यसभा सांसद रुक्मिणी मल्लिक जिन्हें पेशेवर तौर पर कोएल मल्लिक के नाम से जाना जाता है, ने संसद के उच्च सदन से इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले, तृणमूल के तीन सांसदों ने अपनी राज्यसभा सीटों से इस्तीफ़ा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। कोयल मल्लिक का इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है।
राजनीति

कोएल मलिक के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की संख्या घटकर 9 रह गई है। इससे पहले भाजपा के तीन उम्मीदवारों सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाईक ने सोमवार को पश्चिम बंगाल से राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा। अधिकारियों के अनुसार, तीनों नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपने नामांकन पत्र जमा किए। नामांकन दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के साथ विधानसभा स्थित अपने कक्ष में



तीनों उम्मीदवारों के साथ बैठक की।

ये तीनों राज्यसभा सीटें सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाईक के राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा देने तथा तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के बाद रिक्त हुई थीं। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अब वे करीब एक महीने बाद भाजपा के टिकट पर दोबारा संसद पहुंचने के लिए तैयार हैं। तीनों नेता नौ जुलाई को भाजपा में शामिल हुए थे और कुछ ही घंटों के भीतर पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल से राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद यह पहला बड़ा अवसर है, जब तृणमूल के पूर्व नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया है।

इसे इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल करने पर लगी अनौपचारिक रोक उन नेताओं पर लागू नहीं होगी, जिन्हें पार्टी राजनीतिक रूप से विश्वसनीय और भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त मानती है।

सोनिया गांधी के घर पर बैठक के बाद बड़ा एलान

परिसीमन बिल का कांग्रेस करेगी पुरजोर विरोध: जयराम रमेश

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि अगर संसद के आगामी मॉनसून सत्र में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को फिर से पेश किया जाता है, तो पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक ऐसे उपाय के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसे पहले लोकसभा में ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, रमेश ने कहा कि पार्टी ने उन बिलों पर विस्तार से चर्चा की है जिन्हें सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पार्टी को अभी तक सरकार का आधिकारिक विधायी एजेंडा नहीं मिला है और 19 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में उन्हें इसकी जानकारी मिलेगी।

कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने सुना है कि गृह मंत्री परिसीमन बिल को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। 17 अप्रैल को सरकार को इस बिल के लिए दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था, जो एक बड़ी हार थी। वे उस बिल को वापस लाना चाहते हैं। पार्टी का रुख दोहराते हुए रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का रुख हमेशा से साफ रहा है- हम परिसीमन बिल का पुरजोर विरोध करेंगे और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। हम सभी विपक्षी दलों के बीच एकता बनाए रखने की हर संभव कोशिश करेंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी दलों में फूट डालकर कानून पास कराने के लिए ज़रूरी संख्या जुटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि 17 अप्रैल से गृह मंत्री ने एक या दो विपक्षी पार्टियों में फूट डलवाई है। यह संविधान का अपमान है। वे चालाकी से दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चालाक चालों और दूसरी पार्टियों को तोड़कर दो-तिहाई बहुमत हासिल करना संविधान का अपमान है; यह एक दागदार बहुमत होगा। हालांकि, लोकसभा में उनके दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोई संभावना नहीं है।



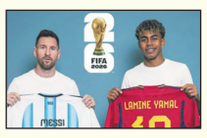
उन्होंने कहा कि हम विपक्षी पार्टियों के संपर्क में हैं; राहुल गांधी संपर्क में हैं, और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उन सभी पार्टियों के संपर्क में हैं जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन बिल का पुरज़ोर विरोध किया था। महिला आरक्षण कानून का ज़िक्र करते हुए रमेश ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन इसे प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने का विरोध करती है।

उन्होंने कहा कि हमने पहले भी, 16 और 17 अप्रैल को, मौजूदा लोकसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने के बारे में अपना रुख़ साफ़ किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में महिलाओं के लिए इस एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान शामिल है... अगर आप 543 सदस्यों वाली लोकसभा का एक-तिहाई हिस्सा निकालें, तो यह 181 होता है। इसलिए, महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान लाइए और हम पूरा समर्थन देंगे। हालाँकि, जो परिसीमन बिल पेश किया गया था, उसे भले ही महिला आरक्षण अधिनियम का नाम दिया गया था, लेकिन असल में वह महिला आरक्षण की आड़ में लाया गया एक खतरनाक परिसीमन बिल था।

खेल
प्रमुख समाचार

19 को फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा

न्यूयॉर्क। विश्व कप फाइनल के लिए मंच सज चुका है जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आक्रमण वाली टीम अर्जेंटीना का सामना स्पेन की उस टीम से होगा जिसकी रक्षापंक्ति की मजबूती का कोई सानी नहीं है। खिताबी मुकाबले में खेल की दो अलग-अलग शैलियों का टकराव देखने को मिलेगा। टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी और मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना रविवार को ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी में स्पेन की मजबूत रक्षात्मक टीम से भिड़ेंगे।



स्पेन के पास मेस्सी को टक्कर देने के लिए लामिन यामल के रूप में युवा स्ट्राइकर है। स्पेन ने मंगलवार को पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को हराया। इस टूर्नामेंट में वापसी करने में माहिर अर्जेंटीना ने बुधवार को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर जीत हासिल की। अर्जेंटीना अपना चौथा खिताब जीतने की कोशिश कर रहा है और ब्राजील के बाद लगातार दो बार विश्व कप चैंपियन बनने की ओर अग्रसर है, जिसने 1958 और 1962 में यह उपलब्धि हासिल की थी।

स्पेन 2010 में जीतने के बाद अपना दूसरा खिताब जीतने की कोशिश कर रहा है। अर्जेंटीना ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 19 गोल किए हैं जबकि टूर्नामेंट में सबसे कम गोल खाने के मामले में स्पेन सबसे आगे है। उसने सिर्फ एक गोल खाया है। दक्षिण अमेरिकी चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन को मार्च के अंत में कतर के दोहा में फाइनलिस्सिमा में एक दूसरे का मुकाबला करना था लेकिन मध्य पूर्व में जारी जंग के कारण यह मैच नहीं हो पाया। और अब संयोग देखिए कि विश्व कप फाइनल में यह दोनों टीम आमने-सामने होंगी।

यह फुटबॉल के वर्तमान और भविष्य के बीच एक मुकाबला होगा। साथ ही उन टीमों के बीच भी मुकाबला होगा जो विश्व कप से पहले फीफा की विश्व रैंकिंग में शीर्ष दो स्थानों पर काबिज थीं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स मामूली बढ़त पर बंद निफ्टी में 5 अंकों की गिरावट

मुंबई। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को भारी उतार-चढ़ाव के बाद लगभग सपाट स्तर पर बंद हुए। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स मात्र 1.44 अंक की मामूली बढ़त के साथ 77,186.87 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 394.26 अंक या 0.51 प्रतिशत उछलकर 77,579.69 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया था, लेकिन समाप्ति से ठीक पहले बिकवाली के दबाव ने इसे वापस नीचे धकेल दिया। दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी भी सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद 5.75 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 24,072.75 के स्तर पर बंद हुआ।

ऑरम प्रॉपटेक ने हाउसिंग डॉट कॉम का किया अधिग्रहण

नई दिल्ली। रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी ऑरम प्रॉपटेक लिमिटेड ने कारोबार के विस्तार के लिए पूर्णत: शेयर आधारित सौदे में संपत्ति वर्गीकृत मंच हाउसिंग डॉट कॉम का अधिग्रहण करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। हाउसिंग डॉट कॉम का स्वामित्व ऑस्ट्रेलिया की आरईए ग्रुप के पास है। मुंबई स्थित ऑरम प्रॉपटेक ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसने पूर्णत: शेयर आधारित लेनदेन के तहत हाउसिंग डॉट कॉम में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए बाध्यकारी शेयर अधिग्रहण समझौता किया है। इस सौदे के तहत ऑरम प्रॉपटेक 1,97,93,309 शेयर जारी करेगी, जो विस्तारित शेयर पूंजी का लगभग 20.5 प्रतिशत होगा। इस लेनदेन के बाद ऑरम प्रॉपटेक में आरईए इंडिया की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 24.9 प्रतिशत हो जाएगी।

12 से निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स पर होगी ट्रेडिंग

नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसे पूंजी बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिलने के बाद वह 12 अगस्त से निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 सूचकांक पर वायदा-विकल्प अनुबंध शुरू करेगा। एनएसई ने बयान में कहा कि वह इक्विटी डेरिवेटिव खंड में इस सूचकांक पर वायदा (फ्यूचर्स) और विकल्प (ऑप्शन) अनुबंध पेश करेगा। सूचकांक शुरुआत में तीन क्रमिक मासिक वायदा और विकल्प अनुबंध चक्र उपलब्ध कराएगा। नकद निपटान वाले इन अनुबंधों की समाप्ति संबंधित माह के अंतिम मंगलवार को होगी। निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 सूचकांक छह महीने की औसत विदेशी निवेश योग्य मुक्त-प्रवाह बाजार पूंजीकरण के आधार पर निफ्टी 500 में शामिल शीर्ष 150 शेयर के प्रदर्शन को दर्शाता है। इस सूचकांक में जून, 2026 तक वित्तीय सेवा क्षेत्र का भार सबसे अधिक 26.15 प्रतिशत था।

सरकार ने डीजल-एटीएफ पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स

नईदिल्ली। पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी भारी सैन्य तनाव और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 16 जुलाई से शुरू होने वाले नए पखवाड़े के लिए डीजल और विमानन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) में भारी बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि, निर्यातकों को राहत देते हुए पेट्रोल पर लगने वाले शुल्क को घटाया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, ये संशोधित दरें 16 जुलाई से तुरंत प्रभावी हो गई हैं। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) बढ़ाकर 8.5 रुपये प्रति लीटर से 15.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

ब्लू इकोनॉमी के जरिये टिकाऊ अर्थव्यवस्था की ओर

रजनीश आनंद

वैश्विक अर्थव्यवस्था आज ऐसे मोड़ पर है, जहां जमीन के संसाधन लगातार सिमटते जा रहे हैं और मिट्टी की घटती उर्वरता से दुनिया का ध्यान पृथ्वी के उस सत्तर प्रतिशत हिस्से की ओर जा रहा है, जो पानी से ढका है। पारंपरिक रूप से हमारी अर्थव्यवस्था जमीन केंद्रित रही है, पर दुनिया अब एक दूरदर्शी बदलाव के रूप में समुद्री संसाधनों के एकीकरण और पर्यावरण शासन की तरफ बढ़ रही है, जिसे हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं।

विश्व बैंक के अनुसार, ब्लू इकोनॉमी का अर्थ महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है। यह केवल समुद्र से पारंपरिक तरीकों से तेल निकालने या मछली पकड़ने तक सीमित नहीं है। यह ऐसा वैज्ञानिक खाका है, जो समुद्री विकास को पर्यावरण के नुकसान से पूरी तरह अलग करता है, ताकि औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाते हुए डेल्टा, तटीय आर्द्रभूमि और एस्चुअरी इकोटोंस जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को बचाया जा सके। जमीन पर आधारित सौर या पवन ऊर्जा के साथ सबसे बड़ी समस्या उनकी अनिश्चितता होती है। जबकि इसके विपरीत, समुद्री संसाधन कहीं अधिक घने और अनुमानित होते हैं। अपतटीय पवन और ज्वारीय ऊर्जा जमीन की तुलना में बहुत अधिक क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ) प्रदान करते हैं। इसी तरह, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन तकनीक समुद्र की ऊपरी गर्म सतह और गहराई के ठंडे पानी के तापमान के अंतर का उपयोग कर बिजली पैदा कर सकती है, जिसे कम तापमान थर्मल अलवणीकरण तकनीक के साथ जोड़कर तटीय क्षेत्रों में मीठे पानी की कमी को बहुत कम लागत पर दूर किया जा सकता है।



इन उपकरणों को खारे पानी, अत्यधिक हाइड्रोलिक दबाव, चक्रवात और सुनामी जैसी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जिससे इसके क्रियान्वयन में भारी पूंजीगत और परिचालन व्यय की चुनौतियां सामने आती हैं। समुद्र के भीतर बिजली का केबल बिछाने और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर लगाने में भारी शुरुआती निवेश की आवश्यकता होती है, और खारे पानी के संक्षारक स्वभाव के कारण रखरखाव की लागत बढ़ जाती है। ये सभी कारक मिलकर तकनीक की लेवलाइज्ड लागत को बढ़ा देते हैं, जिससे प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और पेबैक पीरियड प्रभावित होता है, इसलिए, किसी भी तकनीक को लागू करने से पहले उसके टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल और जैविक व रासायनिक संवेदनशीलता का सटीक आकलन करना अनिवार्य हो जाता है।

इन चुनौतियों के बावजूद ब्लू इकोनॉमी की असली ताकत भविष्य के कार्बन मुक्त उद्योगों के लिए प्रयोगशाला के रूप में काम करने की इसकी क्षमता है। जब अपतटीय पवन से मिलने वाली बिजली से पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, तब ग्रीन हाइड्रोजन का जन्म होता है। इस ग्रीन हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ संश्लेषित करके ग्रीन अमोनिया बनाया जा सकता है। यह शिपिंग उद्योग के लिए एक बेहतरीन कार्बन मुक्त ईंधन है, जिसे आसानी से स्टोर किया जा सकता है। यह वैश्विक उर्वरक बाजार के लिए एक टिकाऊ आधार प्रदान करता है। इसके साथ ही, सीवीड की खेती लोगों, इस ग्रह और मुनाफे के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जो भोजन, पशु चारा और नेट जीरो ईंधन के रूप में काम आती है। जलवायु संकट से निपटने के लिए समुद्र में सक्रिय वैज्ञानिक हस्तक्षेप की भी आवश्यकता है। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग जैसी तकनीकों के जरिये समुद्री हीट वेव्स को कम किया जा सकता है, जो कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक जहाजों का शोर व्हेल और डॉल्फिन के इकोलोकेशन को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी जगह फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या शांत टग्स का उपयोग किया जा सकता है, जो इस ध्वनि आघात को रोक सकता है।

रिमझिम बारिश के बीच दिखा आस्था का महासंगम

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में आयोजित भव्य रथयात्रा महोत्सव में शामिल हुए। दोनों ने विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा पारंपरिक 'छेरा-पहरा' की रस्म निभाते हुए प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की।

इस अवसर पर मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। वैदिक मंत्रोच्चार, भजन-कीर्तन और जयघोष के बीच भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशेष विधि-विधान के साथ मंदिर से रथ तक लाया गया।



सोने की झाड़ू से निभाई छेरा-पहरा की परंपरा

इसके पूर्व राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पारंपरिक रीति से सोने की झाड़ू द्वारा छेरा-पहरा की रस्म निभाकर रथमार्ग का प्रतीकात्मक शुद्धिकरण किया। इसके पश्चात महाप्रभु की प्रतिमाओं को श्रद्धापूर्वक रथ पर विराजित किया गया और रथयात्रा का शुभारंभ हुआ।

इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को रथयात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता, लोकपरंपरा और जन-जन की आस्था का महापर्व है। यह उत्सव समाज को सेवा, समर्पण, समानता और लोककल्याण का संदेश देता है।

खुशहाली और अच्छी वर्षा की कामना

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भगवान जगन्नाथ किसानों के आराध्य और अन्नदाता के रक्षक माने जाते हैं। उनकी कृपा से समय पर वर्षा होती है, खेतों में हरियाली आती है, धान की बालियों में दूध भरता है और किसानों के घरों में समृद्धि का आगमन होता है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि इस वर्ष प्रदेश में भरपूर वर्षा हो, कृषि समृद्ध हो, किसानों की मेहनत सफल हो और छत्तीसगढ़ निरंतर विकास एवं खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ता रहे।

उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का दिव्य आशीर्वाद समस्त प्रदेशवासियों पर बना रहे तथा सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का संचार हो। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हमारी परंपराओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ समाज में सद्भाव, एकता और सामूहिक चेतना को भी नई ऊर्जा प्रदान करते हैं।

हर वर्ष पुरी की तर्ज पर निकलती है रथयात्रा

उल्लेखनीय है कि राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष पुरी की विश्वविख्यात रथयात्रा की तर्ज पर यह आयोजन अत्यंत श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न होता है। छेरा-पहरा की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि भगवान के समक्ष सभी समान हैं और सेवा ही सर्वोच्च धर्म है।उल्लेखनीय है कि ओडिशा का पड़ोसी राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ में भगवान जगन्नाथ के प्रति विशेष श्रद्धा और आस्था रही है। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में रथयात्रा का आयोजन उत्साहपूर्वक किया जाता है। उत्कल संस्कृति और दक्षिण कोसल की सांस्कृतिक परंपराओं के बीच यह पर्व एक सशक्त सेतु का कार्य करता है।इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, विभिन्न निगम-मंडलों एवं आयोगों के अध्यक्षगण, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

प्रदेश में खाद की कमी से बोनी और थरहा का काम प्रभावित हो रहा है : दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि पूरे प्रदेश में खाद की कमी के कारण बोनी और थरहा का काम प्रभावित हो रहा है, किसानी पिछड़ रही है लेकिन सत्ता में बैठे जिम्मेदार केवल फर्जी दावें करके अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं।



खाद की पर्याप्त उपलब्धता के सरकारी दावों को किसानों के साथ भद्दा मज़ाक है। मात्र 24 हजार टन डीएपी के कागजी आबंटन को अपनी उपलब्धि बता कर श्रेय लेने वाले भाजपा नेताओं को यह बताना चाहिए खुद के ही द्वारा तय लक्ष्य 15 लाख 55 हजार मीट्रिक टन में से केवल 7 लाख 27 हजार 833 मीट्रिक टन खाद ही किसानों को दिया गया है जो कि मांग के आधे से भी कम है। सबसे कम वितरण डीएपी और यूरिया का है जो किसानों के मांग की तुलना में चौथाई भी नहीं है। कभी किस्तों में खाद तो कभी टोकन पर देने के तुगलकी फरमान जारी किए, पिछले साल की तुलना में डीएपी में 40 प्रतिशत कटौती और यूरिया 20 प्रतिशत कम देने का आदेश? फिर टोकन सिस्टम वापस ले लिए, तय लक्ष्य का अब तक आधा भी दिए नहीं फिर यह आबंटन अतिरिक्त कैसे? किसानों को ठगना बंद कर समस्या के समाधान पर ध्यान दे सरकार।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह पहला अवसर है जब जुलाई के महीने में भी किसानों की जरूरत के आधे मात्रा में भी खाद का वितरण नहीं किया गया है। पहले अप्रैल के महीने में ही वितरण शुरू हो जाता था और जून के महीने तक वितरण लगभग पूर्ण हो जाता था। मानसून आने से पहले ही सोसायटियों के गोदाम से होकर किसानों तक खाद पहुंच चुका होता था, अभी आबंटन जारी होने का दावा किया गया है, इस किसान विरोधी सरकार को बताना चाहिए कि कब भौतिक अलॉटमेंट होगा? कब रैक लगेगी? सोसायटियों और किसानों तक कब पहुंचेगा? सड़कों की मरम्मत तक नहीं करवा पा रही है यह सरकार, बरसात में अनेकों गाँव पहुंच विहीन हो चुके हैं, ऐसे में वहां के किसान कैसे खेती कर पाएंगे?

मानसून सत्रः सेवाग्राम प्रोजेक्ट पर भूपेश-अजय में बहस

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही जारी है। प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फर्जी ग्रामसभाओं का मामला उठाया। कथित फर्जी ग्रामसभा प्रस्तावों के आधार पर उद्योगों की स्थापना के सवाल पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।

ध्यानाकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने बस्तर संभाग में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संभाग की कई पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। गड़बड़ी करने वाले विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।



जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है। यदि कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

इससे पहले मछुआ नीति, खाद का आवंटन के मुद्दे पर भी सवाल पूछे गए। सेवाग्राम प्रोजेक्ट पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और विधायक अजय चंद्राकर के बीच तीखी बहस हुई। बाद में अपने शब्दों के लिए अजय चंद्राकर ने सदन में खेद जताया। इस पर भूपेश बघेल ने धन्यवाद कहा।

मछुआ नीति की गड़बड़ी पर उठाए सवाल: नेता प्रतिपक्ष ने कहा- वन क्षेत्र के तालाब पर आदिवासी से टैक्स नहीं ले सकते, लेकिन मौजूदा नीति में टैक्स का प्रावधान है।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- मौजूदा नीति 2022 में भूपेश सरकार ने बनाई थी। 10 हजार हेक्टेयर का ठेका पंजीकृत व्यक्ति या संस्था को देने का प्रावधान किया गया। इससे स्थानीय लोग, समुदाय का हक मारा गया। नई नीति में इन सब विसंगतियों को दूर किया जाए।उर्वरक आवंटन का मुद्दा उठा: कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने कुछ स्थानों में लक्ष्य के विरुद्ध ज्यादा खाद देने का आरोप लगाया।

जयंत वैष्णव बने मुख्यमंत्री सुरक्षा के नए पुलिस अधीक्षक

रायपुर। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए आईपीएस अधिकारी जयंत वैष्णव को मुख्यमंत्री सुरक्षा का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। डीजीपी अरुण देव गौतम द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।हाल ही में हुए पुलिस फेरबदल में हरीश राठौर को कोरिया जिले का नया एसपी बनाया गया था। उनके तबादले के बाद से ही सीएम सुरक्षा का यह महत्वपूर्ण पद रिक्त चल रहा था, जिसकी जिम्मेदारी अब जयंत वैष्णव को सौंप दी गई है। दरअसल, मुख्यमंत्री सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे निवर्तमान एसपी हरीश राठौर को सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए कोरिया जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। हरीश राठौर के कोरिया जिला रवाना होने के बाद मुख्यमंत्री की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालने के लिए एक अनुभवी अधिकारी की आवश्यकता थी। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार की हरी झंडी के बाद जयंत वैष्णव के नाम पर मुहर लगाई गई।

स्मार्ट मीटर से नहीं बढ़ता बिजली बिल

रायपुर। स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की शंकाओं को दूर करने के लिए विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर बिजली का बिल नहीं बढ़ाता, बल्कि केवल वास्तविक खपत के आधार पर सटीक बिल तैयार करता है। विभाग का कहना है कि यदि किसी उपभोक्ता का बिल बढ़ा है तो उसका प्रमुख कारण बिजली की अधिक खपत और उच्च टैरिफ स्लैब में पहुंचना है, न कि स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उपभोक्ता को वास्तविक समय में बिजली खपत की जानकारी उपलब्ध कराता है। मोर बिजली ऐप के माध्यम से उपभोक्ता हर आधे घंटे की बिजली खपत देख सकते हैं। इससे यह समझना आसान हो जाता है कि कौन-से विद्युत उपकरण सबसे अधिक बिजली खर्च कर रहे हैं और किन उपायों से खपत कम की जा सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार पहले उपभोक्ताओं को केवल महीने के अंत में बिजली बिल मिलने पर ही खपत



का पता चलता था, जबकि स्मार्ट मीटर में उपभोक्ता पूरे महीने अपनी खपत पर लगातार नजर रख सकते हैं। इससे अनावश्यक बिजली उपयोग पर नियंत्रण संभव होता है और बिल भी कम किया जा सकता है। बिजली विभाग ने बताया कि प्रदेश में बिजली दरें निर्धारित स्लैब के अनुसार लागू होती हैं। शून्य से 100 यूनिट तक 4.40रुपये प्रति यूनिट, 101 से 200 यूनिट तक 4.50 रुपये प्रति यूनिट, 201 से 400 यूनिट तक 6 रुपये प्रति यूनिट 401 से 600 यूनिट तक 7 रुपये,601 यूनिट से अधिक पर 8.80रुपये प्रति यूनिट दर निर्धारित हैं। जैसे ही बिजली खपत बढ़कर अगले स्लैब में पहुंचती है, बिल स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इसका स्मार्ट मीटर से कोई संबंध नहीं है।

विभाग के अनुसार इस वर्ष अप्रैल, मई और जून में भीषण गर्मी के कारण अधिकांश घरों में एसी, कूलर और अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग बढ़ा। इसी वजह से बिजली की खपत बढ़ी और कई उपभोक्ताओं के बिल भी अधिक आए। यह स्थिति मौसम और खपत से जुड़ी है, न कि स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली से। स्मार्ट मीटर का एक बड़ा लाभ यह भी है कि उपभोक्ता अपनी मासिक खपत को 400 यूनिट से नीचे बनाए रखने की योजना पहले से बना सकते हैं। इससे उन्हें राज्य सरकार की हाफ बिजली योजना का लाभ मिलता रहता है। यदि खपत 400 यूनिट से अधिक हो जाती है तो योजना का लाभ प्रभावित होता है और बिल बढ़ जाता है। विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को समय रहते ऐसी स्थिति से बचने का अवसर देता है। बिजली विभाग ने यह भी बताया कि स्मार्ट मीटर से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच में अधिकांश मामलों में मीटर सही पाया गया।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

रायपुर में जमकर बारिश हुई मानसून फिर से सतर्क



रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। गुरुवार शाम राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के मजबूत होने से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। डेमोग्राफ़िक्स आज (16 जुलाई) कई जगहों पर हल्की से मध्यम, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 1 जून से अब तक सामान्य से 29% कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले अच्छी बारिश होने से इस कमी में सुधार आ सकता है।बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में रिकॉर्ड किया गया। रायपुर में गुरुवार दिनभर बादल छाए रहेंगे। शहर का अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग दिवस पर ऑनलाइन कार्यशाला 12 को

रायपुर। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग दिवस (12 अगस्त) के अवसर पर इंडिया स्पेस लैब द्वारा रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट विषय पर ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े हितधारकों के बीच भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा आपदा प्रबंधन में इसके प्रभावी उपयोग की जानकारी प्रदान करना है। कार्यशाला में रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम , अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी, जियो-एआई , ड्रोन मैपिंग, मशीन लर्निंग आधारित अनुप्रयोगों तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े वास्तविक केस स्टडी पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे।कार्यशाला के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सफलतापूर्वक कार्यशाला पूर्ण करने वाले सभी प्रतिभागियों को ई-प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। आयोजकों ने छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, स्वायत्त संस्थाओं, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों से कार्यशाला की जानकारी व्यापक स्तर पर प्रसारित करने का अनुरोध किया है। साथ ही इस सूचना को विभागीय वेबसाइटों, पोर्टलों, सूचना पट्टों, समाचार पत्रिकाओं तथा अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की गई है।

किसान निर्धारित तिथि तक करा लें फसल बीमाः कलेक्टर

रायपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2026 के अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि तक अपने फसलों का बीमा करा लें।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के फसल के बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, स्थानीय आपदाओं (ओलावृष्टि, बादल का फटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली) एवं फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान से फसल को होने वाली क्षति के विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। योजना का लाभ लेने हेतु किसान नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्थान, ग्राहक सेवा केन्द्र (सी.एस.सी) सेंटर में जाकर बीमा करा सकते हैं। खरीफ वर्ष 2026 में मुख्य फसल धान सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर 66 हजार रूपए और धान असिंचित के लिए 49 हजार 500 रूपए प्रति हेक्टेयर की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई है, जिसकी प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत कृषक अंश के रूप में धान सिंचित के लिए 1320 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं धान असिंचित के लिए 990 रूपए प्रति हेक्टेयर है।जिले में धान सिंचित, धान असिंचित के साथ-साथ सोयाबीन, मक्का, अरहर, उड़द, रागी एवं कोदो भी अधिसूचना में शामिल है जिसका बीमा करा सकते हैं।

आरटीई की रिक्त सीटों का प्रकटीकरण 21 जुलाई तक

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में कक्षा पहली की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु तृतीय एवं अंतिम चरण की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाएगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि आरटीई प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया 27 अगस्त 2026 तक हर स्थिति में पूर्ण की जानी अनिवार्य है तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। महत्वपूर्ण तिथियां और समय-सारणी लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्धारित समय-सारणी इस प्रकार है। 17 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक जिला स्तर पर विद्यालयवार आरटीई की रिक्त सीटों का प्रकटीकरण और प्रचार-प्रसार कर सकेंगे। 22 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक पात्र पालक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। 25 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक नोडल प्राचार्यों द्वारा आवेदनों का सूक्ष्म परीक्षण, सत्यापन और पात्र/अपात्र की प्रविष्टि दर्ज करना। 10 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी होना।

मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर को मिलेगा पर्यटन स्थल का दर्जा

रायपुर।चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर को राज्य शासन द्वारा धार्मिक पर्यटन स्थल के लिए रुप में चिन्हांकित किया गया और योजना तैयार होने के बाद इसका क्रियान्वयन कराया जाएगा। यह जानकारी विधायक रामकुमार यादव के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में दिए। विधायक रामकुमार यादव द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में मंत्री अग्रवाल ने बताया कि मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर, ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1521/प.मं./2004 दिनांक 09.06.2004 द्वारा मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर को ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल की श्रेणी में राज्य के चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। विगत दो वर्षों में मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर एवं आसपास के क्षेत्र के विकास हेतु विभाग द्वारा राशि स्वीकृत नहीं की गयी है। शक्तिपीठ कॉरिडोर सर्किट योजना में राज्य के 5 प्रमुख देवी मंदिरों में मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर-चन्द्रपुर शामिल है जिसके विकास हेतु योजना तैयार की जा रही है। योजना तैयार होने उपरान्त इसका क्रियान्वयन कराया जाएगा।



सेवा ग्राम बनाने का उद्देश्य महात्मा गांधी की राम-राज्य की संकल्पना को अक्षुण्य रखना है : चौधरी

नवा रायपुर में प्रस्तावित सेवाग्राम मामला उठा सदन में

रायपुर। पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत नवा रायपुर में सेवाग्राम बनाने का निर्णय कब लिया गया? उसके उद्देश्य क्या हैं? उसके अंतर्गत क्या-क्या कार्य किया जाना है? कितनी राशि का बजट प्रावधान रखा गया है? कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिये व्यय की जा चुकी है? का मामला मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा में उठाया।

वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने सदन को बताया कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण अंतर्गत नवा रायपुर में सेवाग्राम बनाने का निर्णय 10 मार्च 2022 को लिया गया।

प्रस्तावित सेवा ग्राम का उद्देश्य आजादी की लड़ाई के मूल्यों, सिद्धान्तों व आदर्शों तथा महात्मा गांधी जी की आत्म निर्भर की राम-राज्य की संकल्पना को अक्षुण्य रखने तथा भावी पीढ़ी को उन मूल्यों की जानकारी देना तथा संस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं आत्मनिर्भर ग्राम की कल्पना को साकार करने हेतु कारीगरों के प्रशिक्षण करने का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत बायोडायवर्सीटी पार्क, इकोलॉजिकल पॉण्ड, विजिटर सेन्टर प्रेयर हाल, म्यूजियम/एक्जीबिशन-हॉल/गैलरी, लायब्रेरी, स्थानीय क्राफ्ट की दुकानें, एम्पीथियेटर, सेवाश्रम-रिहायशी क्षेत्र यथा प्रशिक्षु के निवास, आर्टिस्ट के निवास, कामन किचन एवं चिकित्सालय, क्लासरूम एवं वर्कशाप, फ्रीडम वॉक एवं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया जैसे कार्य किया जाना है।



उक्त कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में ?08.00 करोड़, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 60.00 करोड, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 61.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। मल्टीपरपज डाईनिग हॉल, सामुदायिक किचन एवं प्रसाधन कक्ष का निर्माण में रू. 3.72 करोड़ का व्यय हुआ है। बायोडायवर्सीटी पार्क, इकोलॉजिकल पॉण्ड, विजिटर सेन्टर प्रेयर हॉल, गैलरी, म्यूजियम / एक्जीबिशन -हॉल / लायब्रेरी, स्थानीय क्राफ्ट की दुकाने, एम्पीथियेटर, सेवाश्रम-रिहायशी क्षेत्र यथा प्रशिक्षु के निवास, आर्टिस्ट के निवास, चिकित्सालय, क्लासरूम एवं वर्कशाप, फ्रीडम वॉक इत्यादि के निर्माण कार्य में रू. 104.05 करोड़ का व्यय हुआ है। समस्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। सेवाग्राम के संचालन हेतु सेटअप स्वीकृत नही किया गया है।

सीएजी ने प्रभावी वित्तीय निगरानीतथा सुशासन को और सुदृढ़ करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की

रायपुर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के. संजय मूर्ति ने मंगलवार को रायपुर स्थित प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़ तथा महालेखाकार , छत्तीसगढ़ कार्यालयों का दौरा कर उनके कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने, डिजिटल परिवर्तन को गति देने और डेटा आधारित लेखा परीक्षा के जरिए वित्तीय जवाबदेही को मजबूत करने पर विशेष बल दिया। दौरे के दौरान सीएजी ने दोनों कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग-अलग समीक्षा बैठकें कीं। इन बैठकों में प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण, क्षमता निर्माण और प्रभावी वित्तीय निगरानी के माध्यम से संस्थागत कार्यप्रणाली तथा सुशासन को और सुदृढ़ करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई।



प्रधान महालेखाकार , छत्तीसगढ़ के कार्यों की समीक्षा करते हुए मूर्ति ने कोषागार निरीक्षण और वित्तीय विश्लेषण में डेटा एनालिटिक्स के व्यापक उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने राजकोषीय संकेतकों, खनिज राजस्व, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में पड़ी अव्ययित राशि की विश्लेषणात्मक निगरानी को और मजबूत करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने सेवा पुस्तिकाओं के शीघ्र डिजिटलीकरण, सेवा अभिलेखों को भविष्य पोर्टल से जोडने, सामान्य भविष्य निधि के डेटा प्रबंधन को सुदृढ़ करने तथा संभागीय लेखा संवर्ग के अधिकारियों के लिए संरचित प्रशिक्षण और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपनाने पर भी बल दिया। सीएजी ने प्रधान महालेखाकार , छत्तीसगढ़ द्वारा प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय प्रशासन और विश्लेषणात्मक समीक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन पहलों से राज्य में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन को और मजबूती मिलेगी।

महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़ के साथ हुई समीक्षा बैठक में मूर्ति ने सोलहवें वित्त आयोग (2026-2031) की अवधि के अनुरूप लेखा परीक्षा रणनीतियों को पुनर्संरेखित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए उपलब्ध कराई जा रही प्रदर्शन आधारित केंद्रीय अनुदान राशि वित्तीय जवाबदेही की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.